● वर्ष-4
● अंक-128
रायपुर, बुधवार
08 जनवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

# समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» घर में लगाएं ये फूल तनाव होगा दूर....

# मोदी-मनमोहन ने नहीं किया सार्वजनिक धन का उपयोग

**नईदिल्ली।** सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जवाब से पता चला है कि न तो वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और न ही दिवंगत पूर्व प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने-अपने कार्यकाल के दौरान दिवाली समारोह के लिए सरकारी धन का उपयोग किया। पुणे स्थित कार्यकर्ता प्रफुल सारदा ने नवंबर 2024 में आरटीआई क्वेरी दायर की, जिसमें डॉ. सिंह जिनका 26 दिसंबर, 2024 को निधन हो गया - और पीएम मोदी दोनों के कार्यकाल के दौरान वार्षिक दिवाली त्योहार के खर्च के बारे में विवरण मांगा गया था।

3 जनवरी को प्राप्त जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत खर्चों पर कोई सार्वजनिक धन खर्च नहीं किया गया था। पीएमओ के अवर सचिव और केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) परवेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत खर्च सरकारी खाते से वहन नहीं किया जाता है। प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत खर्चों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करता है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका की प्रथम महिला जिल बिडेन को 7.5 कैरेट का हीरा उपहार में देने पर विवाद छिड़ गया है। यह हीरा उन्हें पीएम मोदी ने अपनी 2023 की यात्रा के दौरान भेंट किया था। इस उपहार पर अंतरराष्ट्रीय बहस तब छिड़ गई जब अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी कीमत 20,000 अमेरिकी डॉलर आंकी। हालाँकि, भारत के विदेश मंत्रालय ने सुझाव दिया कि रत्न की वास्तविक कीमत बहुत कम है, इसका अनुमान 2 लाख रुपये से कम है, क्योंकि यह प्रयोगशाला में विकसित किया गया है।

## चुनाव याचिका दायर करने के लिए 45 दिन की समयसीमा को चुनौती दी थी

# मेनका की याचिका पर सुनवाई से इनकार

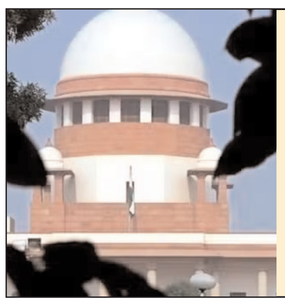

**कोर्ट का, चुनाव याचिका दायर करने के लिए 45 दिन की सीमा को दी थी चुनौती**

**नई दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका दायर करने के लिए 45 दिन की समयसीमा को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि वह कानून बनाने का काम नहीं कर सकता और बाढ़ के लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मेनका गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद की लोकसभा चुनाव में जीत को चुनौती दी थी। निषाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर सीट से जीत हासिल की थी। कोर्ट ने निषाद को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के चुनाव जीतने के बाद 45 दिन की ही समयसीमा होती है, जिसमें याचिका दायर की जा सकती है। यह नियम जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 81 में है। मेनका गांधी को निषाद से 43,174 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस मामले पर सुनवाई नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम कोई नया कानून बनाएं, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि हम 45 दिन की समयसीमा को गलत ठहराएं और इसे 60 या 90 दिन कर दें। लेकिन हम यह नहीं कर सकते।

### मेनका गांधी के वकील ने क्या दलील दी

मेनका गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि वह 1973 में हुए एक फैसले को फिर से देखने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस फैसले में जो 45 दिन की समय सीमा तय की गई थी, वह गलत है और इसे फिर से देखा जाना चाहिए। लूथरा ने यह भी कहा कि यह समयसीमा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए समस्या हो सकती है, जिसने चार आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई हो। हालांकि, बेंच ने कहा कि किसी फैसले को गलत बताने के लिए कोर्ट में सिर्फ नागरिक अपील की जा सकती है।

## सूचना आयुक्त के पदों को जल्द से जल्द भरने की जरूरत- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों पर नकारात्मक रुख अपनाया और केंद्र को तत्काल पदों को भरने का निर्देश दिया। सीआईसी में सूचना आयुक्तों के शीघ्र चयन के लिए कहते हुए जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र से कहा, %इन पदों को जल्द से जल्द भरने की जरूरत है, अन्यथा संस्थान होने का क्या फायदा, अगर हमारे पास काम करने वाले लोग ही नहीं हैं?% पीठ ने सीआईसी और एसआईसी में केवल एक विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्तियों की आलोचना की और इन आयोगों में नौकरशाहों की मौजूदगी पर न्यायिक टिप्पणी करने पर विचार किया, न कि सभी क्षेत्रों के लोगों की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि पूरे आयोग में केवल एक ही श्रेणी के लोग काम करते हैं। हम इस पर और कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज और अन्य की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि 2019 में शीर्ष अदालत ने सीआईसी और एसआईसी में पदों को भरने के लिए मौलिक निर्देश जारी किए थे, लेकिन राज्यों ने चयन प्रक्रिया में देरी की और सूचना के अधिकार अधिनियम को लगभग समाप्त कर दिया। संबंधित सचिवों को बुलाने या जवाब मांगने का न्यायालय से आग्रह करते हुए भूषण ने कहा कि रिक्तियों के कारण इस मंच का उपयोग करने वाले लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

# भूकंप से तिब्बत में भारी तबाही, 95 की मौत

**बीजिंग।** तिब्बत के सबसे पवित्र शहरों में से एक के निकट मंगलवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 95 लोगों की मौत हो गई और 130 अन्य घायल हो गए।

पड़ोसी देश नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसके कारण इमारतें हिलने लगीं और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए।क्षेत्रीय आपदा राहत मुख्यालय के अनुसार, मंगलवार को सुबह नौ बजकर पांच मिनट (चीन के समयानुसार) पर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के शिगाजे शहर की डिंगरी काउंटी में

भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई है।चीन की सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' की खबर के अनुसार, भूकंप के कारण मंगलवार को अपराह्न तीन बजे तक (स्थानीय समयानुसार) 95 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 130 अन्य घायल हुए हैं।चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के लिए हर संभव प्रयास करने के आदेश दिए।शी ने घायलों के उपचार के लिए हरसंभव प्रयास करने का आदेश दिया तथा द्वितीयक आपदाओं (भूकंप के बाद संभावित आपदाओं) को रोकने, प्रभावित निवासियों के समुचित पुनर्वास तथा इसके बाद के कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया।भूकंप के बाद, चीन भूकंप प्रशासन ने स्तर-दो की आपात सेवा प्रतिक्रिया शुरू की तथा आपदा राहत प्रयासों में सहायता के लिए एक कार्य दल को घटनास्थल पर भेजा।केंद्रीय प्राधिकारियों ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र में करीब 22,000 आपदा राहत सामग्री भेजी है, जिनमें तंबू, कोट, रजाई और फोल्डिंग बिस्तर के साथ-साथ ऊंचाई वाले और ठंडे क्षेत्रों के लिए विशेष राहत सामग्री भी शामिल है।घटनास्थल पर 1,500 से अधिक स्थानीय अग्निशमन कर्मियों और बचावकर्मियों को भी भेजा गया है।शिगाजे को शिगास्ते के नाम से भी जाना जाता है।

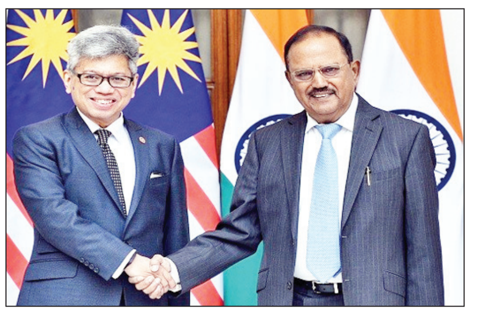

## भारत-मलेशिया के बीच सुरक्षा वार्ता

**नईदिल्ली।** राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ पहली भारत-मलेशिया सुरक्षा वार्ता आयोजित की, जहां दोनों पक्षों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

## ठेकेदार सुरेश चन्द्राकर का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित

**रायपुर।** लोक निर्माण विभाग ने बीजापुर के ठेकेदार सुरेश चन्द्राकर का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उसे दिए गए सभी कार्य निरस्त कर दिए हैं। बस्तर परिक्षेत्र जगदलपुर के विभागीय मुख्य अभियंता की अनुशंसा पर प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा सुरेश चंद्राकर का पंजीयन निलंबित किया गया है। मुख्य अभियंता द्वारा लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत सुरेश चंद्राकर च्अज्ज वर्ग ठेकेदार, बीजापुर के पत्रकार श्री मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने तथा गिरफ्तार किए जाने के कारण उसके पंजीयन को निलंबित किए जाने की अनुशंसा की गई थी। मुख्य अभियंता की अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुए विभाग ने सुरेश चंद्राकर का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं सुरेश चंद्राकर को दिए गए सड़क निर्माण के कार्यों को लंबे समय तक बंद पाए जाने तथा कार्यों की धीमी गति के कारण उसे दिए गए सभी कार्यों को निरस्त कर दिया गया है।

**प्रमुख समाचार**

## एडीजी अमित कुमार को मिला राष्ट्रपति पदक

**रायपुर।** राज्य पुलिस के खुफिया विभाग के प्रमुख एडीजी अमित कुमार को आज नई दिल्ली में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 1998 बैच के आईपीए अमित कुमार आज यह सम्मान नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित कुमार ने दिया। अतिम कुमार को यह सम्मान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में रहते हुए किए गए विशिष्ट कार्य के लिए दिया गया है।

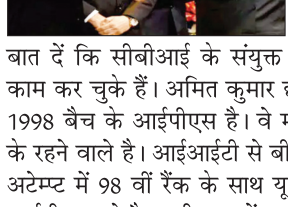

बात दें कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक पद पर काम कर चुके हैं। अमित कुमार छत्तीसगढ़ कैडर के 1998 बैच के आईपीएस है। वे मूलत: बिहार राज्य के रहने वाले है। आईआईटी से बीटेक के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में 98 वीं रैंक के साथ यूपीएससी क्रैक कर आईपीएस बने है। छत्तीसगढ़ में राजधानी व न्यायधानी समेत आधा दर्जन जिलों के एसपी रहने के अलावा सीबीआई में 12 वर्षों तक विभिन्न पदों पर पदस्थ रहकर कई महत्वपूर्ण के सुलझाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव के चारा घोटाले की जांच करने के अलावा डायरेक्ट पीएमओ को रिपोर्ट करने वाले ज्वाइंट डायरेक्टर पॉलिसी के पद पर भी रहे हैं।

## पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाएगी सरकार

**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने का फैसला किया है। पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मृति परिसर के भीतर एक स्थल को चिन्हित करने को मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि, इसकी जानकारी लेखक और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बाबा के लिए एक स्मारक बनाने के उनके सरकार के फैसले के लिए दिल से आभार और कृतज्ञता व्यक्त की। यह और भी अधिक सराहनीय है, क्योंकि हमने इसके लिए नहीं कहा था। प्रधानमंत्री के इस अप्रत्याशित लेकिन सचमुच दयालु भाव से मैं बहुत प्रभावित हूं। अपने दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा- बाबा कहते थे कि राजकीय सम्मान के लिए मांग नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे पेश करना चाहिए। मैं बहुत आभारी हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा की याद में ऐसा किया। इससे बाबा पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अब कहां हैं- सिर्फ तारीफ या आलोचना से परे।

## धार्मिक स्थानों में वीआईपी संस्कृति की आलोचना

**नई दिल्ली।** भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्री मंजुनाथ स्वामी में पूजा करने वाले भक्तों के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए श्री सानिध्य परिसर का उद्घाटन करने के लिए मंगलवार को कर्नाटक में श्री क्षेत्र धर्मस्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने धार्मिक स्थानों पर वीआईपी संस्कृति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हाल के वर्षों में एक सुखद बदलाव बुनियादी ढाँचे का विकास रहा है जो हमारे धार्मिक स्थानों के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी सराहना की जानी चाहिए क्योंकि ये हमारे सभ्यतागत मूल्यों के भी केंद्र हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें धार्मिक संस्थानों में समानता के विचार को फिर से स्थापित करना चाहिए। जब प्राथमिकता दी जाती है, जब किसी को प्राथमिकता दी जाती है, जब हम इसे वीवीआईपी या वीआईपी के रूप में लेबल करते हैं, तो यह समानता की अवधारणा को कमजोर करता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वीआईपी संस्कृति एक विपथन है, समानता के आधार पर देखा जाए तो यह एक घुसपैठ है। इसका समाज में तो क्या धार्मिक स्थलों में भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

## मुझे फिर मुख्यमंत्री आवास से निकाला गया: अतिशी

**नई दिल्ली।** भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उनके तीन महीने के कार्यकाल में दूसरी बार कल रात उन्हें आधिकारिक आवास से बेदखल कर दिया। हालाँकि, पीड्ब्ल्यूडी ने दावों का खंडन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आज आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मुझे तीन महीने में दूसरी बार मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल दिया है। आतिशी ने आगे कहा कि वह किसी भी कीमत पर दिल्ली के लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सोचती है कि वे हमारे घर छीनकर, हमें गाली देकर और मेरे परिवार के बारे में बुरा बोलकर हमें काम करने से रोक देंगे। वे हमारे घर छीन सकते हैं, हमारा काम बंद कर सकते हैं।

## बीपीएससी परीक्षा रद्द करने सुप्रीम कोर्ट का इनकार

**नई दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी, 2025 को कथित पेपर लीक को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया अदालत के रूप में काम नहीं कर सकता है, खासकर जब उच्च न्यायालय में कोई पूर्व याचिका दायर नहीं की गई हो। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह उचित और अधिक शीघ्र होगा कि याचिकाकर्ता अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में परीक्षा रद्द करने और कथित कदाचार की जांच के लिए एक विशेष जांच बोर्ड के गठन की मांग की गई है।

# महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम पर विपक्ष का पाखंड हुआ उजागर

**नईदिल्ली।** हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों ने एक बार फिर विपक्ष की उस प्रवृत्ति को सुर्खियों में ला दिया है, जब भी चुनावी नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते हैं, तो वे ईवीएम पर हंगामा मचाने लगते हैं। सोलापुर के मरकडवाडी गांव में एक अजीबोगरीब घटना, जहां स्थानीय लोगों ने मतपत्रों का उपयोग करके अवैध पुन: चुनाव की योजना बनाई थी, राजनीतिक बयानबाजी से फैली गलत निराशा का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण बन गया है। योजनाबद्ध पुन: चुनाव, जिसे बाद में अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया।

राकांपा (सपा) विधायक उत्तमराव जानकर के समर्थकों के बीच असंतोष के कारण हुआ। जो कुल मिलाकर मालशिरस विधानसभा सीट 13,000 से अधिक के अंतर से जीतने के बावजूद, मार्कवाडी में भाजपा के राम सतपुते से हार गए थे। ईवीएम के बारे में संदेह से उत्तेजित होकर, इन असंतुष्ट ग्रामीणों ने पुनर्मतदान की घोषणा करते हुए बैनर दिखाए, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं मिला। स्थानीय उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने इस कदम को सही ही अवैध और अलोकतांत्रिक करार दिया।

### कांग्रेस ने ही दिया था ईवीएम का उपहार

पूरे देश के सामने ईवीएम को कांग्रेस की सरकार ने ही पेश किया था, फिर भी आज यह उनका पसंदीदा बलि का बकरा बन गया है। जयेश जैसे ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से पाखंड पर सवाल उठाया- ये लोग लोकतंत्र को ही चुनौती दे रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, ईवीएम कांग्रेस द्वारा पेश किया गया था। विपक्ष की कहानी तब ढह

जाती है जब कोई यह मानता है कि जब महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने उन्हीं मशीनों का उपयोग करके लोकसभा चुनाव जीता था तो कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

### मार्कडवाडी के मतदाता सबसे बेहतर जानते हैं

मार्कडवाडी की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। भाजपा के राम सातपुते ने समग्र सीट हारने के बावजूद अपने विकास कार्यों के कारण गांव में काफी लोकप्रियता हासिल की। ग्रामीणों ने सतपुते के समर्थन के लिए ठोस कारणों का हवाला दिया, जैसे कि एक पर्यटक केंद्र स्थापित करने और क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण धन लाने के उनके प्रयास। उन्होंने कहा, भाऊ ने अथक मेहनत की है और 150 वोटों की बढ़त हासिल की है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाई गई लड़की बहिन योजना ने भी मतदाता भावना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि एक और अन्य व्यक्ति ओंकार ने ठीक ही कहा है, भले ही हम मतपत्रों पर वापस जाएं, गलतियाँ संभव हैं। लड़की बहिन योजना के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

### जमीनी हकीकत बनाम राजनीतिक अवसरवाद

ईवीएम छेड़छाड़ के आरोपों से विपक्ष के राजनीतिक अवसरवाद की बू आ रही है। मिथुन जैसे ग्रामीणों ने इस विसंगति पर ज़ोर दिया- अगर कोई मुद्दे थे, तो उन्होंने उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान क्यों नहीं उठाया? यह आक्रोश संविधान विरोधी है। जमीनी स्तर के विकास पर भाजपा के फोकस के साथ जोड़ा जाता है। देवेंद्र फड़नवीस, शिंदे साहब और अजीत दादा के शासन ने महिलाओं के लिए उनकी भ्रष्टाचार मुक्त पहल और कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रशंसा अर्जित की है। जैसा कि आदेश गुप्ता ने जोर देकर कहा, मतदाता अपनी शक्ति को जानते हैं और उन्होंने सतपुते को उनके योगदान के आधार पर चुना है।

### ईवीएम में पूरी तरह पारदर्शिता

जांच करने पर छेड़छाड़ के आरोप धरे के धरे रह जाते हैं। जैसा कि आलोक ने तर्क दिया, अगर ईवीएम में हेरफेर किया गया था, तो लोकसभा चुनाव के दौरान ये आपत्तियां सामने क्यों नहीं आईं? जब परिणाम उनके पक्ष में होते हैं, तो यह स्वीकार्य होता है। जब नहीं होता है, तो वे शिकायत करते हैं। यह दोहरापन विपक्ष की मतदाताओं के साथ रचनात्मक जुड़ाव की कमी और साजिशों पर अत्यधिक निर्भरता को रेखांकित करता है।

### हार स्वीकार करे विपक्ष

विधानसभा चुनाव के बाद ग्रामीणों की पुनर्मतदान की योजना, हालांकि गलत है, यह उजागर करती है कि राजनीतिक आख्यान कितनी आसानी से सार्वजनिक धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। नेताओं को अल्पकालिक लाभ के लिए लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने से बचना चाहिए। मरकडवाडी के लोग बोल चुके हैं- उन्होंने विभाजनकारी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए वोट किया है।

जैसा कि दिनेश ने बुद्धिमानी से कहा, अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई होती, तो हमारे सांसद उम्मीदवार जीत गए होते। लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं की। दूसरों के विपरीत, हम जनादेश का सम्मान करते हैं। अब समय आ गया है कि विपक्ष भी ऐसा ही करे। अंत में, लोकतंत्र तब फलता-फूलता है जब सभी दल प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और शिकायतों पर शासन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतदाताओं ने अपनी पसंद बना ली है- आओ आगे बढ़ें।

# 10 किलो का आईईडी सुकमा में डिफ्यूज, फोर्स को एंबुश में फंसाने की साजिश नाकाम

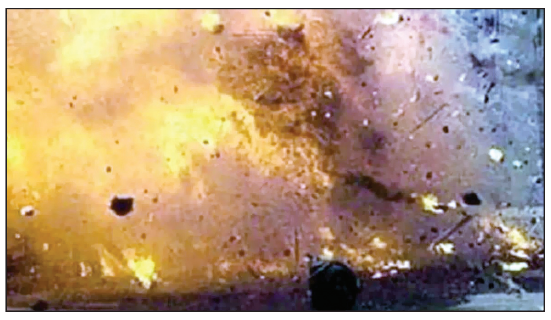

**सुकमा।** एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने 10 किलो का आईईडी बरामद किया। जवानों ने बड़ी सतर्कता के साथ बम को डिफ्यूज कर दिया। सर्च ऑपरेशन पर निकले जवानों को निशाना बनाने के लिए बम को प्लांट किया गया था। कल बीजापुर में हुए आईईडी ब्लास्ट के बाद से जवान पूरी सतर्कता सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान बरत रहे हैं। नक्सलियों ने बम कोंटा के बेलपोच्चो के पास लगाया था।

सुकमा एसपी किरण चव्हाण के मुताबिक जवान रुटीन सर्चिंग पर निकले थे। सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवान शामिल रहे। टीम जब सुकमा के कोंटा इलाके में पहुंची तो उनको आईईडी लगे होने का शक हुआ। जवानों ने बड़ी सतर्कता के साथ गोलापल्ली रोड और बेलपोच्चो के पास डिमाइनिंग का काम शुरु किया। डिमाइनिंग करने के दौरान 10 किलो का घातक बम जमीन में लगा बरामद हुआ। जवानों ने तत्काल एक्सपर्ट की मदद से उसे डिफ्यूज कर दिया।

बीजापुर के कुटरू में कल नक्सलियों ने फोर्स के वाहन को आईईडी विस्फोट कर उड़ा दिया था। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए 60 से सत्तर किलो के आईईडी का इस्तेमाल किया। कल की घटना के बाद से पूरे बस्तर में फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवान कड़ी सतर्कता बरत रहे हैं, सर्चिंग के दौरान जो गाइडलाइन है उसका भी पालन कर रहे हैं।

### बीजापुर में नक्सलियों की सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग

**बीजापुर।** उसूर थाना क्षेत्र में माओवाद विरोधी अभियान के लिए निकले केंद्रीय बल की 196वीं बटालियन के जवानों ने 20 से 22 किलो का आईईडी रिकवर किया। ये आईईडी नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में रखा हुआ था। सुबह करीब साढ़े सात बजे जवानों ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का पता लगाया। सोमवार दोपहर को हुए घातक नक्सली ब्लास्ट से पहले जवानों को ये कामयाबी मिली।

सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईईडी रिकवर कर उसे नष्ट करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा एक बड़ी त्रासदी टल गई, क्योंकि आईईडी का पता लगा लिया गया और उसे नष्ट किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ के जवानों ने कच्ची सड़क के नीचे से आईईडी बरामद करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया। आईईडी का वजन करीब 20-22 किलोग्राम था। इसे बल के बम निरोधक दस्ते ने कुछ घंटों में निष्क्रिय कर दिया और इलाके में यातायात बहाल कर दिया।

## मृतक वाहन चालक के पिता नहीं जानते थे, कि वह पुलिस का वाहन चला रहा

**जगदलपुर।** कुटरू थाना क्षेत्र अंतर्गत बेदरे मार्ग पर ग्राम अम्बेली में नक्सलियों द्वारा किए गये आईईडी धमाके में एक सिविलियन वाहन चालक तुलेश्वर राना उम्र 25 वर्ष निवासी बस्तर जिले के बड़े आरापुर की भी मौत हो गई। इस घटना के बारे में परिजनों को पता ही नहीं था, देर शाम जब बीजापुर पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर घटना की जानकारी दी। पिता को इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि उनका बेटा पुलिस विभाग में वाहन चलाने का काम कर रहा था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बस्तर जिले के कोड़ेनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बस्तर जिले के बड़े आरापुर निवासी कमल साय राना का सबसे छोटा पुत्र तुलेश्वर राना कुछ समय तक नगरनार स्थित एनएमडीसी में वाहन चलाने का काम करता था। अचानक से वहां से कुछ महीने पहले ही पुलिस लाइन में वाहन चलाने का काम करने लगा। वीआईपी दौरा या फिर जवानों को लाने ले जाने का काम तुलेश्वर के द्वारा किया जा रहा था। तुलेश्वर अपने दोस्तों के साथ जगदलपुर में ही एक किराए के मकान में रह रहा था। वह आखिरी बार 22 दिसंबर को अपने घर गया था, जहां अपने परिजनों से बात करने के बाद चला गया था। चार भाई-बहनों में तुलेश्वर को छोड़कर सभी भाई-बहन की शादी हो चुकी है। सोमवार सुबह भी तुलेश्वर की अपनी मां से बात हुई, उसके बाद उसने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के स्टेटस में अपनी एक फोटो भी शेयर की, लेकिन सोमवार की दोपहर को तुलेश्वर को बिल्कुल भी अहसास नहीं हुआ कि आज के बाद वह अपने घर नहीं जा पाएगा, नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से आठ डीआरजी जवान के साथ ही वाहन चालक तुलेश्वर राना ने भी अपनी जान गंवा दी। मृतक वाहन चालक तुलेश्वर राना का क्षत-विक्षत शव घटनास्थल से 200 मीटर दूर बरामद किया गया।

## दंतेवाड़ा में पीसीसी चीफ ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा

**बीजापुर।** बीजापुर में सोमवार को जिले के कुटरु के अम्बेली में नक्सली घटना में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने दंतेवाड़ा पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अराजकता माहौल फैला हुआ है। यहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हम सरकार से सवाल करते है, कि आखिर यहां सरकार कौन चला रहा है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार दिल्ली से चल रही है, या नागपुर कि बिहार से चल रही है ? सरकार का कोई मुखिया नहीं है। सरकार भगवान भरोसे चल रही है। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अराजकता का माहौल फैला हुआ है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ विपक्षी नेताओं को डराने के लिए यहां का कानून बना हुआ है। जनता की जानमाल की सुरक्षा के लिए नहीं। उन्होंने गृहमंत्री को हवा में उड़ने वाला बताते हुए बोले उनमें गंभीरता नहीं है। अगर थोड़ी भी गंभीरता उनमें होती तो हमारे जवानों की जान बच सकती थी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। पीसीसी चीफ बैज ने आगे कहा कि हम चाहते है, नक्सलवाद का खात्मा हो, मगर किसी निर्दोष आदिवासियों को मार कर नहीं। जवानों की जान लापरवाही से जाए ऐसे शहादत नहीं। ये सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। बैज ने आगे कहा कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, इसलिए इतनी बड़ी घटना हुई। उन्होंने शहीद जवानों को नमन कर उन्हें श्रदांजलि अर्पित की।

# आदिवासियों को ही निशाना बना रहे नक्सली

## शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी कर रहे वंचित

**रायपुर।** बुधराम कोरसा, हरीश कोर्राम, सोमडू वेट्टी, सुदर्शन वेट्टी, डूम्मा मरकाम, पण्डरू राम पोयाय, बामन सोढ़ी ये वे जवान हैं, जिन्हें नक्सलियों ने सोमवार को बीजापुर जिले में कुटुरू में आईईडी ब्लास्ट के जरिए एक ही पल में शहीद बना दिया। डीआरजी के इन तमाम जवानों में एक चीज कॉमन थी कि ये आदिवासी थे। कुल मिलाकर आदिवासी हितों की रक्षा करने की बात करने वाले नक्सली अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आदिवासियों को ही निशाना बना रहे हैं।

सोमवार को मारे गए डीआरजी के जवानों में से सभी 30-35 साल के बीच के थे। कोई दंतेवाड़ा जिले का तो कोई बीजापुर जिले का रहने वाला था। सभी का अपना भरा-पूरा परिवार था, किसी के छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो किसी के बूढ़े मां-बाप। परिवार का सहारा बनने ध्येय से बल में शामिल हुए इन आदिवासी जवानों की शहादत के बाद पैदा हुई शून्यता से परिजन कैसे निपटेंगे, ये तो वही बता सकते हैं। कोई भी सरकारी आर्थिक मदद इन जवानों की याद को परिजनों के मनो-मस्तिष्क से हटा नहीं सकती है।

ऐसा नहीं है कि नक्सलियों ने केवल सोमवार को किए आईईडी ब्लास्ट में आदिवासियों को अकाल मौत दी हो। अगर नक्सलियों का पूरा इतिहास खंगाले तो पाएंगे कि आदिवासी हितों की रक्षा करने के लिए आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन को सुरक्षित रखने के नाम पर आदिवासियों को ही निशाना बनाया है। न केवल जवान आदिवासियों को समय से पहले काल-कलवित किया हो, या फिर जो सुविधाएं ड्ड सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल-कूद में अवसर जैसे दूसरे क्षेत्र के लोगों के लिए सामान्य है, उससे पूरे आदिवासी वर्ग को वंचित किया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहला काम नक्सलियों को वार्ता के लिए आमंत्रित करने का किया था, बिना शर्त। लेकिन नक्सली हमेशा की तरह मुंह छिपाते रहे। यही नहीं इस दौरान नक्सलियों ने ऐसा कोई काम किया, जिससे आभास हो कि नक्सलियों को वाकई में सुविधाओं से वंचित दूर-दराज के क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों की हितों की रक्षा के लिए कोई काम किया हो। नक्सली न तो आदिवासियों को शिक्षा दे सकते हैं, न ही स्वास्थ्य। बिजली-पानी-सड़क जैसी सुविधा देने की बात तो बहुत दूर की है।

सवाल यह है कि नक्सली कब तक अपने काले कामों को अंजाम देने के लिए आदिवासियों के नाम का उपयोग करते रहेंगे। कब तक मानवाधिकार की दुहाई देने वाले आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय समाजसेवी, स्वयं सेवी संगठन अथवा आदिवासी संगठन सरकार पर निशाना साधने की बजाए मासूम आदिवासियों की नृशंस हत्या पर नक्सलियों के खिलाफ अपनी बात कहेंगे। जबाव है शायद कभी नहीं, क्योंकि यह केवल बस्तर, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र की ही बात नहीं है। यह एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड़यंत्र है, भारत के खिलाफ, जिसमें बड़े-बड़े नक्सली नेता खुद प्यादा बने हुए हैं।

# कोरबा समेत पूरे प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद, कानून व्यवस्था ठप: महंत

## कोरबा में व्यापारी की हत्या के बाद भय का माहौल, नेता प्रतिपक्ष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की

**कोरबा।** कोरबा के रिहायशी इलाके लालू राम कॉलोनी में दो नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर सर्राफा व्यवसायी गोपाल राय सोनी की हत्या कर दी थी। मंगलवार की सुबह छत्तीसगढ़ के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान चरणदास महंत ने कहा कि कोरबा समेत प्रदेश भर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्हें यह हौसला कहां से मिल रहा है यह पता लगाने की जरूरत है। इस तरह की घटना से लोगों में भय का माहौल है।

डॉ चरणदास महंत ने घटना को बेहद निंदनीय बताया है।उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही अपराधियों को पकड़ लेगी। मैंने भी उन्हें जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करने को कहा है। पुलिस वालों को तत्काल अलर्ट होने की जरूरत है। यहां के आम नागरिक भयभीत हैं। इस तरह से सरेआम बीच बाजार घर के अंदर जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो लोगों को भय तो होगा।

डॉ चरणदास महंत ने कहा सिर्फ कोरबा में नहीं बल्कि प्रदेश भर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कानून व्यवस्था का हाल बेहद बुरा है। सरकार को सोचना चाहिए कि इसे ठीक कैसे किया जाए। अपनी कमियों का पता लगाना चाहिए। इससे भी बड़ी-बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे बलोदाबाजार हो बलरामपुर हो या कवर्धा हो। अपराधियों को हौसला कहां से मिल रहा है। यह तो मुझे पता नहीं है। लेकिन इसे ठीक करने की जरूरत है।

बस्तर में आईईडी ब्लास्ट में जवान शहीद हो गए हैं। इस मामले की डॉ महंत ने से इंटेलिजेंस का फेलुअर बताया है। यह भी कहा कि जिस स्थान पर भारत के गृह मंत्री आते हैं।वहां इस तरह के घटना होना बेहद आपत्तिजनक है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यह और भी गंभीर बात है, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और कहां चूक हो रही है, कहां गलती हो रही है। यह सरकार को पता लगाना चाहिए और इसे दूर किया जाना चाहिए।

कोरबा में 24 घंटे के भीतर क्राइम कि दूसरी बड़ी वारदात हुई है। रविवार को सराफा व्यवसायी के घर में घुसकर हत्या करने के बाद सोमवार के देर रात को कोरबा क्षेत्र में एक उपसरपंच को गोली मार दी गई है। जिससे वह बुरी तरह से घायल हुए हैं। जिससे कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इस तरह की घटनाओं पर महंत ने कहा है कि सरेआम बाजार में जिस तरह से नशा के पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं। सूखा नशा लोग करने लगे हैं। यह 75 फीसदी घटनाओं के पीछे का बड़ा कारण है। सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। सभी का सहयोग अपराधों को समाप्त करने की दिशा में होना चाहिए। हम लोग भी अपनी तरफ से सलाह दे रहे हैं।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

### एयरपोर्ट की विकास कार्यों के संबंध में कलेक्टर ने की बैठक

**जगदलपुर।** कलेक्टर श्री हरिस एस की अध्यक्षता में मां दन्तेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर की विकास कार्यों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में एयरपोर्ट परिसर में बैठक किया गया। बैठक में जगदलपुर एयरपोर्ट के रनवे रिर्कापेटिंग, आईसोलेशन बे का निर्माण कार्य, पैरीमीटर रोड का चैड़ीकरण कार्य,कंसरटिना कोइल को बदलने संबंधी कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने हेतु 10 जनवरी तक टेंडर प्रक्रिया करवाने के निर्देश कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। इसके अलावा रनवे मार्किंग,रनवे लाईट का कार्य अविलंब करने कहा। बैठक में सीआरपीएफ बैरेक का अन्य जगह स्थानांतरित करने, एयरपोर्ट के समीप कचरा सीवेज डंपिंग तथा जलाने पर रोक, भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अवैध निर्माण पर रोक, होमगार्ड के परेड ग्राउंड में स्थित गेट को परेड उपरांत बंद करने, वार्षिक लायसेंस नवीनीकरण हेतु डीजीसीए का निरीक्षण की तैयारी हेतु आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने, रनवे 24 केश गेट के समीप एक कक्ष निर्माण आदि के संबंध में चर्चा किया गया।

### बीएसपी ने क्वाटर खाली करने भेजा नोटिस

**दुर्ग।** भिलाई इस्पात संयंत्र के सैकड़ों रिटायर्ड कर्मचारी मंगलवार को टीए बिल्डिंग के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। बीएसपी क्वाटर खाली कराने के बीएसपी प्रबंधन के फैसले का रिटायर्ड कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया है। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित टीए बिल्डिंग में 100 से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों ने बीएसपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीएसपी के रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में 35 से 40 साल नौकरी करने के बाद वो रिटायर हुए हैं। जिस मकान में वो रहते हैं, अब बीएसपी प्रबंधन उसे खाली कराना चाहती है। बीएसपी रिटायर्ड कर्मचारी संघ अध्यक्ष सुरेश चंद्र ने कहा बीएसपी में 35 से 40 साल सेवा दिया, अब हमें मकान से बेदखल किया जा रहा है। हमने 9 से 10 लाख रुपए बीएसपी में जमा किया है। मकान के किराए को लेकर 32 प्रतिशत से ज्यादा किराया हम बीएसपी प्रबंधन को हर महीना देते हैं। फिर भी हमें बीएसपी प्रबंधन ने मकान खाली करने का नोटिस दिया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं।

### बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों से कैसे होगी शहर की सुरक्षा

**कांकेर।** कांकेर शहर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 3 साल पहले चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। लेकिन अब ये सीसीटीवी कैमरे अब केवल शो-पीस बन कर रह गए हैं और धूल फांक रहे हैं। हालत यह है कि अगर चौराहों पर कोई बड़ी घटना हो जाए तो पुलिस को दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों का सहारा लेना पड़ता है। कांकेर शहर के सभी महत्वपूर्ण चौराहों पर पुलिस विभाग ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। इन कैमरों की मदद से पुलिस शहर के सभी चौराहों पर नजर रखती थी। कई अपराधिक मामलों में पुलिस को इसका लाभ भी मिला। जब कभी चौराहों पर जाम लगती तो तत्काल थाना से जवान पहुंच जाते थे। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों पर भी पुलिस की नजर रहती थी। लेकिन वक्त के साथ चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे धीरे धीरे खराब होते गए। व्यापारी पप्पू मोटवानी ने कहा आए दिन शहर में चोरी की वारदात हो रही है। पहले गली मुहल्ले में चोरी होती थी। अब शहर के मुख्य मार्ग में चोरी की वारदात हो रही है।

### दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

**जशपुर।** जशपुर में क्रिसमस के मौके पर एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म और उसके अश्लील वीडियो को वायरल करने के मामले में तपकरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी रक्षित खाखा को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। पीड़िता ने बताया कि 24 दिसंबर 2024 को क्रिसमस मनाने अपने घर आई थी। 25 दिसंबर की सुबह, जब वह घर के बाहर खड़ी थी, तभी उसका पुराना परिचित रक्षित खाखा उसे जबरदस्ती अपनी स्कूटी में बैठाकर अपने घर ले गया। आरोपी ने अपने घर की छत वाले कमरे में ले जाकर पीड़िता के हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बनाया। हवस के दरिंदे ने पीड़िता को 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अपने घर में बंधक बनाकर दरिंदगी करता रहा । छठवें दिन 31 दिसंबर को लावाकेरा - खारीबहार के रास्ते में छोड़ दिया। जाने से पहले उसने धमकी दी कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया, तो वह वीडियो वायरल कर देगा।

### छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे ज्यादा ठंड सरगुजा संभाग में है। पूरे संभाग में शीतलहर चल रही है। प्रदेश में अगले दो दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी, जिससे ठंडी और बढ़ेगी। हालांकि अभी दो दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं सोमवार को प्रदेश में सबसे ठंडा अंबिकापुर रहा। यहां 7.1 डिग्री न्यून्यतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान दुर्ग में 30.6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना है। इससे प्रदेश में ठंड में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही आउटर इलाकों में कोहरा छाए रहन के साथ ही कड़ाके की ठंड और ठिठुरन का अहसास होने वाला है। हालांकि अभी दो दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। मौसम में बदलाव नहीं होगा। दो दिनों के बाद मौसम मी बदलाव होगा।

# तस्करी का नया तरीका, सजी-धजी पिकअप में लोडेड ड्रम देखकर पुलिस को हुआ शक

- **जांच में पकड़ाया गांजा, आरोपी गिरफ्तार**

**गरियाबंद।** पुलिस की कार्रवाई से बचने गांजा तस्कर नए-नए तरीके अपना रहे हैं। सजी-धजी पिकअप वाहन के जरिए गांजा तस्करी कर रहे आरोपी के पास 83 किलो गांजा बरामद किया गया। आरोपी जगदीश भाटिया ओडिसा से गांजा लेकर रायपुर की ओर जा रहा था। पुलिस आरोपी जगदीश को गिरफ्तार कर नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, गांजा तस्कर ने पैटर्न बदलकर गांजे की तस्करी कर रहा था। ओडिसा से सजी धजी पिकअप वाहन में गांजा लेकर रायपुर की ओर जा रहा था। सीमा से निकल गांजा से लोड पिकअप वाहन देवभोग, इन्दागांव, जुगाड़, मैनपुर, नवागढ़ थाना को पार कर गरियाबंद पहुंच गया था। तस्कर गांजा अपनी ही वाहन से गांजा तस्करी को अंजाम दे रहा था।

इस दौरान गरियाबंद पुलिस को प्लास्टिक ड्रम लोडेड वाहन ओडिसा से रायपुर की ओर जाते देख शक हुआ। जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो प्लास्टिक ड्रम में गांजा मिला। तीन प्लास्टिक ड्रम में से 83 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत 8 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिसके खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

बता दें कि ओडिसा के जयपुर, कोरापुट के पहाड़ी इलाके में गांजा की खेती होती है। जो आसानी से 300 किलो में कालाहांडी जिले के बिचौलियों को डीलवर होता है। कालाहांडी के बिचौलिए 100 से 200 रुपए किलो का मार्जिन रखकर इसे बाहरी पैडलर को खपाते हैं।

# लखपति दीदी दिव्या गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों होंगी सम्मानित

**राजनांदगांव।** छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव की दिव्या निषाद आज हर किसी के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बन गई हैं। उनके कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास ने उन्हें वह मुकाम दिलाया है, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। दिव्या ने सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता पाई, बल्कि अपने गांव और आसपास के क्षेत्र में अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। अब उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करते हुए, उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा।

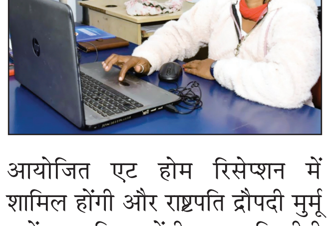

राजनांदगांव जिले के ग्राम कुसमी की लखपति दीदी दिव्या निषाद 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल होंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। लखपति दीदी दिव्या निषाद ने विपरीत और संघर्षपूर्ण स्थिति में भी हार नहीं मानी और राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर सफलता की नई इबारत लिखी है। दिव्या निषाद ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सम्मान की बात है कि लखपति दीदी के तौर पर राष्ट्रपति भवन जाने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि यह जानकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और घर में सभी खुश हैं।

लखपति दीदी योजना, विष्णुदेव साय सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (स्।त्रह्य) के माध्यम से जोड़कर छोटे उद्योगों, कृषि आधारित कार्यों और अन्य उद्यमशीलता गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। दिव्या निषाद ने इस योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया।

दिव्या की लगन और सफलता ने उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी प्रेरक कहानी ने सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचा और उन्हें राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया। इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए दिव्या अब राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार ग्रहण करेंगी।

दिव्या निषाद ने साबित कर दिया है कि अगर सही दिशा और अवसर मिले, तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। लखपति दीदी योजना ने न केवल दिव्या की जिंदगी बदली, बल्कि उनके माध्यम से सैकड़ों अन्य महिलाओं को भी स्वावलंबी बनने का मार्ग दिखाया। आज दिव्या न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का प्रतीक बन गई हैं। उनका सम्मान पूरे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा और यह कहानी हर महिला को अपने सपनों के प्रति मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी।

## संक्षिप्त समाचार

### दिल्ली में गिरीश पंकज को मिलेगा वेद व्यास सम्मान

**रायपुर।** राही रैंकिंग द्वारा जारी की गई सौ लेखकों की सूची में दसवें क्रम पर आने वाले शहर के चर्चित लेखक गिरीश पंकज को नई दिल्ली में 1 मार्च, 2025 को वेद व्यास सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान इंडिया नेटबुक्स-बीपीए फाउंडेशन द्वारा दिल्ली के होटल क्राउन प्लाजा, मयूर विहार एक्सटेंशन दिया जायेगा। सम्मान की सूचना आज जारी की गई। हिंदी भाषा क्षेत्र के परम विशिष्ट साहित्य विभूषण सम्मान श्रेणी गिरीश पंकज के अलावा संतोष श्रीवास्तव (वागेश्वरी सम्मान), हरीश नवल ( भारतेन्दु हरिश्चंद्र सम्मान), दिविक रमेश (कालिदास सम्मान) भी सम्मानित किए जाएँगे। क्षेत्रीय भाषा के लिए विजय दान देथा सम्मान- सी पी देवल (राजस्थानी), पन्नालाल पटेल सम्मान -केशुभाई देसाई (गुजराती) तथा विनेश्वर ब्रम्ह सम्मान-यू जी ब्रम्ह (असमिया) को प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गिरीश पंकज की साढ़े आठ हजार पृष्ठ वाली बीस खण्डों की रचनावली अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। लेखक को उत्तर प्रदेश सरकार का ढाई लाख रुपये की राशि वाला महत्वपूर्ण सम्मान साहित्य भूषण तथा हिंदी भवन नई दिल्ली द्वारा दिया जाने वाला एक लाख की राशि वाला व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हो चुका है।

### रायपुर नगर निगम महापौर के लिए मीनल चौबे की दावेदारी सबसे मजबूत

**रायपुर।** राजधानी रायपुर नगर निगम महापौर के लिए आरक्षण की प्रक्रिया के बाद महिला सामान्य घोषित होते ही अब प्रत्याशी कौन को लेकर कयास लगाये जाने लगे हैं। कांग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन भाजपा से सबसे मजबूत दावेदार के रूप में निवृतमान नगर निगम परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे मीनल चौबे का नाम लिया जा रहा है। कई बार के पार्षद, जिला व प्रदेश महिला भाजपा मोर्चा में विभिन्न पदों पर कार्य करने के साथ शुरु से ही तेज तर्रार कार्यशैली व सभी गुटों से बेहतर तालमेल रखने के कारण मीनल चौबे के नाम पर आसानी से सहमति बन जाने की संभावना है। नगर निगम के कामकाज का अच्छा खासा अनुभव भी मीनल के पास है। कुछ माह पहले हुए दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में उसके वार्ड से सर्वाधिक लीड भी मिला था।

### आचार संहिता लगेगी एक साथ पर अलग-अलग तिथि में होंगे पंचायत व निकाय चुनाव : अरुण साव

**रायपुर।** निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि निकाय और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है। दोनों ही चुनाव के लिए आचार संहिता एक साथ लगेगी लेकिन मतदान अलग-अलग चुनाव कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध होंगे। साव ने कहा कि अगले दो दिनों में निकाय और पंचायत आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को सरकार चुनाव कराने की सिफारिश करेगी।

### सुरेश चंद्राकर के सभी ठेके निरस्त, लाइसेंस हुआ रद्द

**रायपुर।** राज्य शासन ने मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के खिलाफ आज एक और कड़ा कदम उठाते हुए जहां उसको आबंटित हुए सारे ठेके निरस्त कर दिए वहीं दूसरी ओर उसके ठेकेदारी कार्य के लाइसेंस को रद्द कर दिया जिसके चलते अब वह किसी भी प्रकार के शासकीय कार्यों को करने के लिए अक्षम रहेगा। बताया जाता है कि आरोपी सुरेश चंद्राकर की कंपनी को क्लास वन का ठेकेदारी का पंजीयन मिला हुआ था जिसके चलते वह राज्य शासन के साथ - साथ केंद्रीय शासन के ठेको को लेने का भी पात्र था। उल्लेखनीय है कि बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की 1 जनवरी को निर्मम हत्या कर दी गई थी और इस मामले में चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जिसमें सुरेश चंद्राकर प्रमुख आरोपी है।

### पॉवर कंपनी में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर डॉ.अबीर व डॉ.सुरभि द्वारा जांच व उपचार

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी डंगनिया औषधालय में निश्शुल्क दंत एवं ईएनटी (कान, नाक एवं गला) परीक्षण शिविर रायपुर नेत्र चिकित्सालय एवं डॉ. मिश्रा हॉस्पिटल के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एच.एल. पंचारी, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. इंदु साहू, डॉ. निलेश सिंह एवं चिकित्साधिकारी डॉ. श्वेता जैन उपस्थित थे। शिविर में दंत विशेषज्ञ डॉ. अबीर मिश्र एवं ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. सुरभि मिश्र ने लगभग 90 लोगों का परीक्षण किया। पॉवर कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए इस शिविर में दंत तथा कान,नाक,गला की बीमारियों के संबंध में जागरूकता लाने की पहल की गई। डॉ. अबीर मिश्र ने नियमित दाँत जाँच और सक्रिय मौखिक स्वास्थ्य देखभाल की महत्ता पर जोर दिया। नई तकनीक से होने वाले उपचारों के विषय में भी लोगों को जागरूक किया गया। इसी प्रकार डॉ. सुरभि ने कान,नाक, गला की बीमारियों की नई प्रवृत्तियों और रोकथाम के उपायों के संबंध में चर्चा की।

# मुख्यमंत्री साय ने शहीद जवानों को पुष्पचक्र अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि

## किसी भी हाल में हिंसा और आतंक को सहन नहीं किया जाएगा, नक्सलियों के खात्मे के लिए अभियान निरंतर रहेगा जारी

**दंतेवाड़ा।** मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को दंतेवाड़ा के कारली पुलिस लाइन में सोमवार को बीजापुर जिले के कुटरू-बेदरे मार्ग पर ग्राम अंबेली में आईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों एवं वाहन चालक के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढाढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कदम पर राज्य सरकार उनके साथ है।

उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा, वन मंत्री एवं प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप, विधायक दंतेवाड़ा श्री चैतराम अटामी, विधायक बीजापुर श्री विक्रम मण्डावी, पूर्व सांसद श्री दीपक बैज, पूर्व विधायक श्रीमती देवती कर्मा सहित डीजीपी श्री अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, एडीजीपी श्री विवेकानंद सिन्हा, कमिश्नर बस्तर श्री डोमन सिंह, आईजी बस्तर रेंज श्री सुंदरराज पी., डीआईजी द्वय श्री कमलोचन कश्यप एवं श्री अमित काम्बले, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय सहित पुलिस एवं सीआरपीएफ के अधिकारी तथा अन्य जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा शहीद जवानों एवं वाहन चालक के पार्थिव शव पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।

मुख्यमंत्री साय सहित उपमुख्यमंत्री एवं वन मंत्री ने शहीद जवान बामन सोढ़ी के पार्थिव शरीर को कंधा देकर उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया। साथ ही अन्य शहीद जवानों एवं वाहन चालक के पार्थिव शव को उनके गृह ग्राम रवाना किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजापुर के कुटरू क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा किया गया कायराना हमला न केवल हमारे जवानों पर, बल्कि लोकतंत्र और शांति के मूल्यों पर प्रहार है। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खात्मे के लिए अभियान निरंतर जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसी भी हाल में हिंसा और आतंक को सहन नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार बस्तर संभाग में शांति स्थापित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और मार्च 2026 तक प्रदेश में नक्सलवाद समाप्त होकर ही रहेगा। उल्लेखनीय है कि बीजापुर जिले के कुटरू क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट के चपेट में आने से डीआरजी के 8 जवान सहित एक वाहन चालक शहीद हो गए।

### डीजीपी अशोक जुनेजा समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने किया घटनास्थल का दौरा

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कुटरू थाना क्षेत्र के ग्राम अम्बेली में हुए आईईडी धमाके में आठ जवान बलिदान हो गए। इसके साथ ही एक आम वाहन चालाक भी शहीद हो गए। इस घटना के बाद सीआरपीएफ के महानिदेशक वितुल कुमार छत्तीसगढ़ पहुंचे। वे बीजापुर में हुए नक्सली हमले की समीक्षा करेंगे। साथ ही शिविरों का भी दौरा कर सकते हैं।

दूसरी ओर राज्य के डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजीपी विवेकानंद, आईजी सीआरपीएफ राकेश अग्रवाल, आईजी बस्तर सुंदरराज और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया।

वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर आईईडी विस्फोट में बलिदान हुए आठ जवानों और उनके चालक को पुष्पांजलि अर्पित की व शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की।

## एम्स में नौकरी लगाने के नाम पर 3.37 लाख ठगी

**रायपुर।** सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक के माध्यम से युवती ने युवक से दोस्ती की और वह उसे एम्स रायपुर में नर्स की नौकरी लगाने के नाम पर 3.37 लाख रूपए वसूल कर फरार हो गया। ठगी की शिकार हुई युवती ने आमानाका थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भाठागांव निवासी युवती दुर्गेश्वरी साहू का आरडीए कॉलोनी सरोना निवासी रितेश्वर भुमरकर से फेसबुक पर परिचय हुआ था। गहरी दोस्ती होने के बाद युवती ने नौकरी लगाने की बात कही। रितेश्वर ने एम्स में अपना परिचय होने और स्टाफ नर्स की नौकरी लगाने का भरोसा दिलाया और इस पर एम्स प्रबंधन के लोगों को लेनदेन के लिए दुर्गेश्वरी से पैसे खर्च होने की भी बात कही। युवती ने भी खर्च देने सहमत हुई और रितेश्वर ने अपने बताए खातों में 29-3 से 26-7-24 के बीच अलग अलग दिन कुल 3.37 लाख रूपए डिपाजिट कराया और अब तक नौकरी न लगने पर दुर्गेश्वरी ने पैसे वापस देने की बात कही तो वह ना-नुकर करने लगा।

## पत्रकार मुकेश के जिंदा रहते और मरने के बाद भी कांग्रेस ने किया बहिष्कार : भाजपा

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। बीजेपी ने कहा कि बस्तर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के दौरे के दौरान कांग्रेसियों ने उनका गर्जजोशी से स्वागत किया। बैज खुद को लड्डुओं से तौलवा रहे थे। आतिशबाजी करवा रहे थे। ढोल-नगाड़े बजवा रहे थे। खुद पर फूलों की बारिश करवा रहे थे। नारेबाजी हो रही थी। कांग्रेस की ओर से बहिष्कृत पत्रकार दिवंगत मुकेश चंद्रकार की हत्या के बाद जश्न मना रहे थे। कांग्रेसी नेता अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए,लेकिन जश्न मनाते भी उन्हें शर्म नहीं आई।

बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस ब्रीफ में एक लेटर को दिखाते हुए कहा कि 29 अप्रैल 2024 को कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटी जिला बीजापुर के लेटरपेड में पत्र निकाल कर दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्रकार पर झूठे आरोप

लगाकर सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित कर उनका बहिष्कार करने का एलान किया था।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रीवास्तव ने कहा कि 4 जनवरी 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तय कार्यक्रम जारी किया गया था, उसमें उनका रात्रि विश्राम कांकेर यानी कि बस्तर ही था। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी इसी तारीख को जगदलपुर (बस्तर) में थे। उसके बावजूद ये दोनों नेता मुकेश चंद्रकार की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए और न ही कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। कांग्रेस ने एक सच्चे पत्रकार का जीवित रहते भी बहिष्कार किया और मृत्यु के बाद भी बहिष्कार किया। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? लोकतंत्र और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है, यह फिर से प्रमाणित हुआ।

श्रीवास्तव ने कहा कि इससे भी अधिक शर्मनाक और क्या हो सकता है कि एक तरफ बस्तर गमगीन था दूसरी ओर कांग्रेस जश्न मना रही थी। मुकेश चंद्रकार की निर्ममता से हत्या के बाद जहां बस्तर सहित पूरा छत्तीसगढ़ शोकमग्न था, बस्तर में मुकेश चंद्रकार को अंतिम विदाई देने सभी लोगों ने स्वस्फूर्त अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद कर रखे थे। वहीं उसी बस्तर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज खुद को लड्डुओं से तुलवा रहे थे। आतिशबाजी करवा रहे थे, ढोल-नगाड़े बजवा रहे थे, खुद पर फूलों की बारिश करवा रहे थे, नारेबाजी हो रही थी। कांग्रेस में मानो कांग्रेस नेता द्वारा कांग्रेस द्वारा बहिष्कृत पत्रकार स्व. मुकेश चंद्रकार की हत्या के बाद जश्न का माहौल नजर आ रहा था। कांग्रेसी नेता अंतिम संस्कार में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन यह जश्न मनाते भी उन्हें शर्म नहीं आई।

श्रीवास्तव ने कहा कि इससे अमानवीय, संवेदनहीन, निर्मम, नृशंस, निर्दयतापूर्ण, असभ्य, अशालीन, असामाजिक, कुकृत्य-दुष्कृत्य, जितने भी खराब शब्द हो सकते हैं। वे सारे शब्द कांग्रेस की राजनीतिक अपसंस्कृति के आगे बौने हैं। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अब तक एक सच्चे पत्रकार को अपमानित करने के लिए माफी नहीं मांगी है। इससे शर्मनाक दृश्य किसी भी प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में देखा नहीं गया है। बेशर्मी की पराकाष्ठा तो यह है कि युवा पत्रकार की निर्ममता से हत्या करने वाले कांग्रेस नेता सुरेश चंद्रकार को अब तक कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित तक नहीं किया है।

# नगरीय निकाय के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू होते ही मचा बवाल

## भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने चक्रानुक्रम प्रक्रिया पर उठाए सवाल

**रायपुर।** प्रदेश के विभिन्न निकायों के लिए होने वाले चुनाव के लिए महापौर पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होते ही हंगामा मच गया। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान रायपुर नगर निगम में दो बार सामान्य के बाद चक्रानुक्रम प्रक्रिया को लेकर बवाल मच गया। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने चक्रानुक्रम के लिए तय साल को लेकर सवाल उठाया।

दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10।30 बजे आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई। 14 नगर निगम, 53 नगर पालिका और 125 नगर पंचायत मिलाकर कुल 192 नगरीय निकाय के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण प्रक्रिया होगी। पहले यह प्रक्रिया 27 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन तकनीकी अड़चनों की वजह से तारीख आगे बढ़ती गई।

जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद में चल रही आरक्षण प्रक्रिया के दौरान रायपुर नगर निगम में दो बार सामान्य के बाद शुरू हुई चक्रानुक्रम प्रक्रिया को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में सवाल उठाए। भाजपा की मीनल चौबे और प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने तो कांग्रेस के प्रमोद दुबे ने भी आरक्षण को लेकर सवाल उठाए। पार्षद मृत्युंजय दुबे ने कहा कि एसटी और एससी के साथ अन्याय हो रहा है।

बता दें कि रायपुर निगर निगम में अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट आरक्षित होंगी, वहीं अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए एक सीट आरक्षित होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नगर निगम में चार सीटें आरक्षित होंगी, इनमें से एक सीट महिला के लिए आरक्षित रहेगी। इसके अलावा सात सीटें सामान्य रहेंगी, जिनमें से एक सीट महिला के लिए आरक्षित होगी। इस तरह के नगर निगमों की 14 सीटों में से 5 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।

## 20 लाख किसानों को धान खरीदी के एवज में 22 हजार 864 करोड़ रुपये का भुगतान

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। अब तक लगभग 102 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 20 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 22 हजार 864 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।

प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय के लिए टोकन की सुविधा ऑनलाइन एप (टोकन तुंहर हांथ) और उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है।धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स की ओर से धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक कुल धान खरीदी का 78 प्रतिशत धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, इसके एवज में 46.47 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 06 जनवरी 2025 को 69 हजार 922 किसानों से 3.53 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 81 हजार 556 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 75 हजार 907 टोकन जारी किया गया है।राज्य सरकार की ओर से इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

# महिला शिक्षकों की बिगड़ी तबीयत

### ■ अनशन पर हैं बीएड डिग्री वाले सहायक शिक्षक

**रायपुर।** बीएड डिग्री वाले सहायक शिक्षकों का आंदोलन 14 दिसंबर से चल रहा है। सहायक शिक्षक बर्खास्त किए जाने के बाद से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नया रायपुर के तूता में आज प्रदर्शन में शामिल दो महिला शिक्षकों की तबीयत बिगड़ गई। महिला शिक्षकों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदर्शन स्थल के पास किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद नहीं हैं।

प्रदर्शन में शामिल लोगों की शिकायत है कि प्रदर्शन वाली जगह पर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। शिक्षकों का आरोप है कि महिला शिक्षकों की जब तबीयत बिगड़ी तो 108 एंबुलेंस को फोन कर बुलाना पड़ा। दोनों महिला शिक्षकों को अभनपुर के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की मांग है कि उनको वापस काम पर रखा जाए या समायोजित किया जाए।

मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी शिक्षकों ने दी है। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगें हैं सेवा सुरक्षा प्रदान करना और क्ा्श्वस्र डिग्री वाले सहायक शिक्षकों का समायोजन सुनिश्चित करना। शिक्षकों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार को जल्द उचित फैसला लेना चाहिए।

करीब 3000 से ज्यादा क्ा्श्वस्र डिग्री वाले सहायक शिक्षकों को सरकार ने बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्तगी के बाद से शिक्षक रायपुर के तूता में 14 दिसंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। बीते दिनों भूपेश बघेल प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं।

# ऑल इंडिया स्टील कॉनक्लेव 02 का आयोजन 10 और 11 को

### ■ सीएम साय करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ

**रायपुर।** दो दिवसीय ऑल इंडिया स्टील कॉनक्लेव 2 का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 5 स्टार हॉटल मेफेयर लेक रिसार्ट में 10 और 11 जनवरी को किया जाएगा। जिसमें 17 राज्यों से 1500 प्रतिनिधि शामिल हो रहें है। सेकेन्डरी स्टील में राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा आयोजन करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला है। इसके आयोजक है छत्तीसगढ़ स्टील रि-रोलर्स एसोसिएशन और सहयोगी है, छत्तीसगढ़ स्पॉज आयरन मैन्युफैक्चरर्स जिएशन व छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन।

छत्तीसगढ़ स्टील रि-रोलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय त्रिपाठी, महासचिव बांकेबिहारी अग्रवाल और इवेन्ट चेयरमैन रमेश अग्रवाल और को-चेयरमैन अमित अग्रवाल ने संयुक्त पत्रकारवार्ता में बताया कि भारत पहले ही 2030 तक 300 मिलियन स्टील उत्पादन क्षमता के लक्ष्य के 150 मिलियन टन के आधे रास्ते को पार कर चुका है। आने वाले वर्षों में हम यहां से कहां तक जायेगें यही इस कॉनक्लेव का मुख्य फोकस विषय रहेगा।

जैसे कि मालूम हो लौह अयस्क से समृद्ध छत्तीसगढ़ भारत में तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राज्य है और देश के कच्चे उत्पादन में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है। 10 प्रतिशत पेलेट और 20 प्रतिशत स्पॉज आयरन की हिस्सेदारी राष्ट्रीय स्तर के कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का है।

उन्होंने बताया की प्रथम दिवस 10 जनवरी को कॉनक्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इस्पात मंत्री एच।डी। कुमार स्वामी के द्वारा सुबह 10।30 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद बृजमोहन अग्रवाल व अन्य अतिथि की उपस्थिति अपेक्षित है। उद्घाटन पश्चात एक से सवा घंटे का अलग-अलग सत्र होगा, जिसमें विषय के विषेषज्ञ अपनी बात रखेगें। क्वालिटी कंट्रोल और तकनीकी विषय पर भी विषेश रूप से चर्चा होगी और समस्याओं पर बात होगी। साथ ही प्रौद्योगिकी विषेशज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा 17 राज्यों से लगभग 1500 प्रतिनिधि कॉनक्लेव में शामिल होगें, प्रमुखतरू महाराष्ट्र, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, पंजाब जैसे राज्य हैं। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र, एसईसीएल, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, एनएमडीसी जैसे बड़ी कंपनियों के उच्चाधिकारी भी शामिल होगें। 10 जनवरी की शाम सांस्कृतिक संध्या में मीट ब्रदर्स ग्रुप मुंबई अपनी प्रस्तुति देगें कॉनक्लेव में चूंकि देश भर से लोग हिस्सा ले रहे है इस लिये राष्ट्रीय स्तर पर स्टील निर्माताओं के साथ नेटवर्किंग बनेगा इसलिए ऑल इंडिया स्टील कॉनक्लेव का मुख्य फोकस प्वाइंट है अवसर और चुनौती दो दिन के इस कॉनक्लेव में भारत के इस्पात उद्योग के नए अवसरों और बदलते बाजार की गतिशीलता पर केंद्रित चर्चा भी होगी राज्य व केन्द्र सरकार की इंडस्ट्री से जुडी पॉलिसी पर बात रखी जाएगी।

दूसरे दिन 11 जनवरी को समापन सत्र में अतिथिगण शामिल होगें, इसी दिन शाम में मोटिवेशनल सत्र रखा गया है जिसमें बॉलीवुड के प्रख्यात लेखक, गीतकार पद्मश्री जावेद अखतर अपना प्रेरक उदबोधन देगें, पश्चात बाहर से आये प्रतिनिधियों का औद्योगिक भ्रमण का भी कार्यक्रम है। पूरा विश्वास है कि दो दिन का यह ऑल इंडिया स्टील कॉनक्लेव इस सेक्टर के लिये मील का पत्थर साबित होगा और छत्तीसगढ़ को स्टील मेकिंग का हब बनाने में मार्ग प्रशस्त करेगा। कार्यक्रम के प्रथम दिन देश के प्रख्यात डायमंड बैरन, सावजी भाई ढोलकिया का एक घंटे का प्रेरक उद्बोधन रहेगा।

सावजी भाई ढोलकिया आपने समाज सेवा के लिये प्रख्यात है, इन्होने अपने कर्मचारियों को अनगिनत कारें, मकान, जेवर इत्यादि देकर उनका जीवन आसान करने और कई गावों में पानी की व्यवस्था और सामाजिक उत्थान के लिये अनेक कार्य किये है, उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इसके अलावा एक घंटे का मांईड और सोल के लिये ड्रम बजा कर कैसे जागृत किया जाता है यह कार्यक्रम भी समायोजित है। कार्यक्रम में देश भर से लगभग 125 निर्माता अपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेस भी प्रदर्शित करेगें, जिसका लाभ कॉनक्लेव में आने वाले सभी को एक छत के नीचे मिल सकेगा। एक्जीविशन प्रदर्शनी के लिये अलग से एक 30 हजार फुट का डोम बनाया जा रहा है। यह कॉनक्लेव में आने वाले सभी निर्माता होंगे जो लोहे के क्षेत्र में कार्यरत है स छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना के अपार संभावना है, बाहर से आने वाले सभी को यहां की औद्योगिक पॉलिसी के बारे में भी जानकारी दी जायेगी, जिससे उन्हे छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने या विस्तार करने में मदद मिलेगा। अलग-अलग विषयों पर व्याख्यान होगा, जिसे राज्य शासन के उच्चाधिकारी भी अपनी उपस्थिति से इसे और सार्थक करेगें। कॉनक्लेव को आयोजित करने वाली संस्था छत्तीसगढ़ स्टील रि-रोलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय त्रिपाठी महासचिव बांकेबिहारी अग्रवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम देश और प्रदेश में होनी वाला सबसे विशाल और भव्य कार्यक्रम होगा।

# पाकिस्तान-बांग्लादेश की डगमगाती भारत नीति?

**राजेश बादल**

भारत के खिलाफ उसके पूरब और पश्चिम के दोनों पड़ोसी छद्म पैदा करने की नई नीति अपना रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान अब भारत को भरमाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वह कामयाब होगा अथवा नहीं- कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह पक्का है कि अब तक अदृश्य रही हिंदुस्तान की घेराबंदी अब साफ नजर आने लगी है। भारतीय विदेश नीति नियंताओं के लिए यह बड़ी चुनौती है। चुनौती यह भी है कि इस मामले में भारत को अकेले ही इसका समाधान खोजना होगा, जबकि घेराबंदी करने वालों को चीन और अमेरिका दोनों का समर्थन प्राप्त है। हिंदुस्तान अपने दम पर इसका उत्तर देने की कोशिश कर रहा है। मगर नहीं कहा जा सकता कि कूटनीतिक प्रयास कारगर होंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन का कूटनीति में कोई भरोसा नहीं दिखाई देता। एक सप्ताह पहले बांग्लादेश के सेना प्रमुख वाकर-उज-जमान ने अपने संदेश से सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, 'भारत से हमारा रिश्ता बेहद खास है। हम कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। भारत हमारा महत्वपूर्ण पड़ोसी है और ढाका कई मायनों में नई दिल्ली पर निर्भर है। बांग्लादेश से कई लोग इलाज के लिए भारत जाते हैं। भारत से बहुत सारा सामान मिलता है।' बांग्लादेश के बड़े राष्ट्रीय समाचार पत्र प्रोथोम आलो से बातचीत में जनरल वाकर-उज-जमान ने कहा कि बांग्लादेश ऐसा कुछ नहीं करेगा जो भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ हो। भारत और बांग्लादेश अपने हितों का समान ख्याल रखते आए हैं और रखते रहेंगे। दोनों मुल्कों के बीच लेन-देन का रिश्ता है। यह संबंध बिना भेदभाव के जारी रहना चाहिए। अब देखिए इसके उलट बांग्लादेश की सेना का एक रवैया। एक तरफ सेना प्रमुख यह बयान देते हैं तो दूसरी तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान से 53 बरस पुरानी नीति खत्म कर देता है और पाकिस्तान से समझौता करता है कि वह बांग्लादेश की फौज को प्रशिक्षण देने के लिए मेजर जनरल रैंक के अफसरों को बांग्लादेश भेजे। यह समझौता अगले महीने से अमल में आ जाएगा। कमाल की विदेश नीति है। जिस सेना ने बांग्लादेश में खून की नदियां बहाई हों, लाखों औरतों के साथ दुष्कर्म किया हो, अनगिनत बच्चों को मौत के घाट उतार दिया हो और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हों अब वही सेना अपनी क्रूरता का पाठ पढ़ाने बांग्लादेश जा रही है! इसका क्या अर्थ लगाया जाए? इसी कड़ी में एक और सूचना यह भी है कि बांग्लादेश की न्यायिक सेवा के करीब 50 अधिकारी और न्यायाधीश भोपाल की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेने आ रहे थे। बांग्ला सरकार ने अब उन्हें आने से रोक दिया है। यह प्रशिक्षण दस से बीस फरवरी तक होना था और इसमें जिला स्तर तक के सभी न्यायाधीश आने वाले थे। अब शायद वे पाकिस्तान जा सकते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इतने गंभीर और नीति विषयक निर्णय ले रही है। यह ताज्जुब का विषय है। जाहिर है कि पर्दे के पीछे कोई शक्ति सक्रिय है, जो भारतीय उपमहाद्वीप को अपने रिमोट से संचालित करना चाहती है। बांग्लादेश के बाद आते हैं पाकिस्तान पर। मुल्क के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ का एक टेलीविजन इंटरव्यू इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। इस साक्षात्कार में रक्षा मंत्री कहते हैं कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था। वे यहीं नहीं रुकते और कहते हैं कि महमूद गजनवी ने सिर्फ धन-जायदाद लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किए थे। वे अपने देश की शिक्षा प्रणाली पर हमला बोलते हैं। रक्षा मंत्री यह कहते हुए पोल खोलते हैं कि सारे देश के नागरिकों को स्कूली किताबों में यही बताया और पढ़ाया जाता रहा है कि अफगानिस्तान से आया सुल्तान महमूद गजनवी हमारा नायक था। उसने हजार साल पहले सोमनाथ में एक हिंदू मंदिर पर आक्रमण किया था। अब पाकिस्तान के राजनेता और नौकरशाही इस बात पर बहस कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति अचानक भारत को पसंद आने वाली बातें क्यों कर रहा है? इस देश ने 2012 में अपनी कम दूरी तक मार करने वाली बैलेस्टिक मिसाइल का नाम गजनवी रखा था तो अब रक्षा मंत्री ने महमूद गजनवी की आलोचना क्यों की?

# नेताओं की बढ़ती सम्पत्ति

**योगेंद्र योगी**

भारत में 12.9 करोड़ लोगों को एक वक्त का खाना भी ठीक तरह से मयस्सर नहीं होता और नेताओं की सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती सम्पत्ति इनकी गरीबी का उपहास उड़ा रही है। इस पर भी तुर्रा यह है कि देश के नेता आम जनता के लिए काम करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 931 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू दूसरे नंबर पर हैं। उनके पास 332 करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तीसरे नंबर पर हैं। उनके पास 51 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। यह खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट में किया गया है। देश के 31 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1,630 करोड़ रुपये है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रति मुख्यमंत्री की औसत संपत्ति 52.59 करोड़ रुपये है। भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय या एनएनआई 2023-2024 के लिए लगभग 1,85,854 रुपये थी, जबकि एक मुख्यमंत्री की औसत स्व-आय 13,64,310 रुपये है, जो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का लगभग 7.3 गुना है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ 15 लाख रुपये की संपत्ति के साथ सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 55 लाख रुपये की संपत्ति के साथ सूची में दूसरे सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन 1.18 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ तीसरे सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्रियों की इस सम्पत्ति का खुलासा चुनाव आयोग में दिए गए सम्पत्ति के ब्यौरे से हुआ है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि जो जानकारी दी है, वह सही या कुछ छिपाया गया है। दरअसल देश के नेता चुनाव आयोग को वही जानकारी देते हैं, जिसे वे आयकर रिटर्न में भरते हैं। देश में आयकर रिटर्न भरने वाले भी आयकर और प्रवर्तन निदेशालय के जाल में फंसते रहे हैं। सिर्फ रिटर्न फाइल कर लेने मात्र से किसी की सम्पत्ति या आय दूध की धुली नहीं हो जाती। यदि ऐसा ही होता तो देश के सैकड़ों नेता ईडी, सीबीआई और आयकर के लपेटे में नहीं आते। हालांकि इनके जाल में फंसने के बाद नेता यही राग अलापते रहे हैं कि विपक्ष में होने के कारण उन्हें जानबूझ कर फंसाया गया है।

विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण केंद्र में सत्तारुढ़ भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर भी सवाल उठते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सत्तारुढ भाजपा और उसके सहयोगियों में सभी ईमानदार हैं। चन्द्रबाबू नायडू और नीतिश कुमार के समर्थन से बहुमत में केंद्र की भाजपा सरकार में क्या इतना साहस है कि इनके दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कोई कार्रवाई कर सके। क्या यह संभव है कि इन दोनों दलों के नेताओं के भ्रष्टाचार की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों को नहीं हो।

यही वजह है कि जांच एजेंसियों पर दुर्भावना से कार्रवाई करने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि जिन विपक्षी नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया, उनके मामले रफा-दफा कर दिए गए। 2014 से 2022 तक ईडी के निशाने पर रहे क़रीब 95 फ़ीसदी यानी 115 नेता विपक्ष से थे। हालांकि ये आंकड़े 2022 तक के ही हैं। इसके बाद 2023 में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और इस दौरान विपक्षी दलों ने अलग-अलग राज्यों पर हुई ईडी, सीबीआई की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया था। वर्ष 2004-14 में 26 नेताओं से ईडी ने पूछताछ की थी। इनमें क़रीब 54 फ़ीसदी यानी 14 नेता विपक्ष से थे। यह संभव है कि मुख्यमंत्रियों और दूसरे नेताओं ने सम्पत्ति व्यवसायों के जरिए अर्जित की हो, या फिर पुश्तैनी हो। इसके बावजूद इतनी भारी सम्पत्ति होना देश में गरीबी की जीवन रेखा से नीचे रहने वालों को मुंह तो चिढ़ाती है। जबकि नेता आम लोगों के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं। वर्ष 2023 बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया के सभी गरीब लोगों में से एक तिहाई से अधिक दक्षिण एशिया में रहते हैं- जो लगभग 12.9 करोड़ लोग हैं। भारत इस संख्या में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो अत्यधिक गरीबी में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2.15 डॉलर की दर से अत्यधिक गरीबी तय की जाती है, जबकि 3.65 डॉलर निम्न-मध्यम आय श्रेणी में आता है, तथा 6.85 डॉलर उच्च-मध्यम आय श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। वैश्विक निर्धारित गरीबी रेखा 3.65 डॉलर प्रति व्यक्ति है।

भारत का योगदान वैश्विक गरीबी दर में मामूली वृद्धि के 40 प्रतिशत के बराबर है, जो 23.6 प्रतिशत से बढ़कर 24.1 प्रतिशत हो गई है। भारत में गरीबी दर मिटाने के मामले में केरल सबसे आगे है। केरल में सिर्फ़ 0.71 प्रतिशत आबादी गरीब है। वहीं, बिहार, झारखंड, और उत्तर प्रदेश में गरीबी दर सबसे ज़्यादा है। बिहार में 51.91 प्रतिशत, झारखंड में 42.16 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत आबादी गरीबी में रहती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के मुताबिक, भारत को 127 देशों में 105वां स्थान मिला। भारत, अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, और बांग्लादेश से भी पीछे है। भारत में भुखमरी की वजह से अक्सर मौत भी हो जाती है। भुखमरी के कारण बच्चों और वयस्कों में कुपोषण, बौनापन, और दुर्बलता हो सकती है। भुखमरी सिर्फ़ भोजन तक सीमित नहीं है, यह सरकार की ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में विफलता को दर्शाता है। भारत में भुखमरी की समस्या मुख्य रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश में है। इन राज्यों में से, बिहार और उत्तर प्रदेश में भारत की कुल भूखी आबादी का एक तिहाई हिस्सा है।

भारत में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं है, जिसके विभाग को सौ प्रतिशत भ्रष्टाचार से मुक्त कहा जा सकता है। राज्यों में चाहे किसी भी दल की सरकारें हों, हर पार्टी सत्ता में आने के बाद यही दावा करती है कि भ्रष्टाचार को जड़मूल से मिटाया जाएगा। सत्ता में आते ही यह वादा हवा हो जाता है। जब कभी कोई भ्रष्ट कार्मिक पकड़ा जाता है, तब सरकार यही दावा करती है कि किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, किन्तु यह दावा कभी नहीं करती कि जिस विभाग का आरोपी पकड़ा गया है, वह विभाग अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है।

देश में भ्रष्टाचार, गरीबी और भुखमरी के बीच नेताओं की बढ़ती हुई सम्पत्ति में बेशक सीधा कोई संबंध न हो किन्तु सवाल तो उठना लाजिमी है। यक्ष प्रश्न यही है कि करोड़ों की आबादी के पास दो वक्त का खाना नहीं है तो नेताओं की सम्पत्ति आखिर कैसे बढ़ रही है। ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है, जिनके आर्थिक हैसीयत राजनीति में आने से पहले आम लोगों जैसी थी, किन्तु जनप्रतिनिधि और मंत्री बनते ही उनकी सम्पत्ति में उछाल आ गया। देश में जब तक गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याएं रहेंगी तब तक नेताओं की सम्पत्ति देशहित के दावों की धज्जियां उड़ाती रहेंगी।

**पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय**

# वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

**(गतांक से आगे...)**

यदि इदं हि शब्द के पदपूरक हि को पुराण से बलात्संयुक्त करके यह ही अर्थ भी कर लिया जावे तो भी अष्टादश पुराणों के व्यासकृत होने में कुछ बाधा नहीं पहुँचती; क्योंकि पुरानी कथायों का संग्रहात्मक ग्रन्थ होने से महाभारत को भी उपचारात् पुराण कहा जा सकता है।

जैसे लोक में शूरवीर पुरुष को यह तो सिद्ध है ऐसा कह देने से दुनियाँ में सिंह नाम कोई जानवर होता ही नहीं- यह समझ लेना भ्रम है, इसी प्रकार महाभारत को पुराण कह देने से और पुराणों के न होने की बात है। इसलिए महाभारत के अतिरिक्त ब्राह्म आदि अठारह ग्रन्थों की ही मुख्य पुराण संज्ञा है और महर्षि व्यास जी इतके निर्माता हैं ।

(15) लिङ्गपुराण अध्याय 64 में लिखा है कि वशिष्ठ और पुलस्त्य के वरदान से विष्णु-पुराण पराशर जी ने बनाया है, यथा- अथ तस्य पुलस्त्यस्य वशिष्ठस्य च धीमतः। प्रसादाद्वैष्णवं चक्रे पुराणं वै पराशरः।। इसलिए विष्णुपुराण व्यासकृत नहीं।

(16) यह आक्षेप अतीव विचित्र है। प्रतिवादी अब तक केवल ऐसे हेतु या हेत्वाभास देता आया है कि जिनसे पुराण व्यासकृत न होकर आधुनिक सिद्ध हो जाएं, परन्तु इस आक्षेप के हेतु से स्वयं ही विष्णुपुराण को व्यास जी से भी पुराना मानता है अर्थात्- प्रतिवादी के कथनानुसार उक्त पुराण व्यासकृत नहीं, बल्कि उनके भी पिता जी का बनाया हुवा है।

हम पूर्व सिद्ध कर चुके हैं कि वर्तमान अष्टादश पुराण व्यासजी से पूर्व भी रूपान्तर और नामान्तर में विद्यमान थे तथा इनके मुख्य श्रोता वक्ता चिरन्तन मन्त्रद्रष्टा ऋषिजन ही थे। ऐसी दशा में विष्णुपुराण का पराशरकृत होना हमारे लिये और भी इष्टापत्ति है।

क्रमशः ...

# विदुर के गुप्त-संदेश ने बचाए पांडवों के प्राण

**आशुतोष गर्ग**

दुर्योधन के सुझाव पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दे दी। वारणावत भेजकर दुर्योधन पांडवों को मरवाना चाहता था। उसने अपने मंत्री पुरोचन से कहा, 'पांडव कुछ दिन तक वारणावत में रहेंगे। तुम पहले ही वहां चले जाओ और नगर के छोर पर सन, सर्जरस (राल) और लकड़ी आदि से ऐसा भवन बनवाओ, जो चिंगारी लगते ही भस्म हो जाए। उसकी भीतों पर घी, तेल, चर्बी और लाख मिली हुई मिट्टी का लेप करा देना। फिर उस भवन में कुंती, पांडव आदि के रहने का प्रबंध कर देना। वे सब निश्चिंत होकर सो जाएं, तो तुम उसमें आग लगा देना। इस तरह जब वे अपने घर में ही जल जाएंगे, तो हमारी निंदा भी नहीं होगी।'

पुरोचन ने वारणावत जाकर दुर्योधन की आज्ञानुसार, एक महल तैयार करवाया। इस बीच पांडव वारणावत जाने की तैयारी में जुट गए। यात्रा आरंभ करने से पूर्व विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कहा- एक ऐसा अस्त्र है, जो लोहे का तो नहीं है, परंतु शरीर को नष्ट कर सकता है। यदि शत्रु के इस दांव को कोई समझ ले, तो वह मृत्यु से बच सकता है। (अर्थात शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार किया है, जो आग से भड़क उठने वाले पदार्थों से बना है।)

विदुर का यह संकेत युधिष्ठिर ने समझ लिया था...इसके बाद पांडव, वारणावत की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर ने भवन को चारों ओर से देखकर कहा, 'इस घर का एक-एक कोना आग भड़काने वाली सामग्री से बना है। घी, लाख और चर्बी की मिश्रित गंध से यही प्रमाणित होता है। शत्रु ने बड़ी चतुराई से इसका निर्माण किया है, ताकि हम जब सो रहे हों, तो वह इसे जला दे, परंतु विदुर ने पहले ही यह जान लिया था और तभी उन्होंने हमें गुप्त संदेश द्वारा इसकी सूचना दे दी। अब हमें यहां रहकर रास्तों का पता लगाना चाहिए और फिर एक सुरंग बनाकर हम यहां से निकल जाएंगे।'

इस बीच विदुर ने एक सुरंग खोदने वाले विश्वासपात्र को पांडवों के पास भेजा। उसने आते ही लाक्षागृह के अंदर से एक सुरंग बनाने का काम आरंभ कर दिया। इस कार्य को एक वर्ष बीत गया था। पुरोचन ने देखा कि पांडव भवन में निश्चिंत होकर रहने लगे हैं। पुरोचन को प्रसन्न देखकर युधिष्ठिर समझ गया कि वह भवन में आग लगाने वाला है। एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण-भोज कराया। जब सब खा-पीकर चले गए, तब संयोगवश एक भील स्त्री अपने पांच पुत्रों के साथ भोजन मांगने आई। पांडवों ने उन्हें भोजन और मदिरा दी। उसके बाद वे सब लाक्षागृह में ही सो गए। पुरोचन भी वहीं सो रहा था। तभी भीमसेन ने भवन में आग लगा दी, जिसमें भील स्त्री का पूरा परिवार और पुरोचन आदि सब लोग जलकर मर गए। उनके शव जलकर भस्म हो गए थे, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पाया और दुर्योधन बहुत समय तक यही समझकर खुश होता रहा कि पांडव लाक्षागृह की आग में मारे गए। इस तरह विदुर के गुप्त संदेश का पालन करके पांडव अपनी माता कुंती के साथ सुरंग में से सुरक्षित निकल गए।

# युद्ध एवं आतंक से जूझती दुनिया में शांति का उजाला हो

**ललित गर्ग**

नव वर्ष 2025 की शुरुआत दुनिया के लिए शांति, अमनचैन, अयुद्ध और समृद्धि का वर्ष बनने की कामना के साथ हुई लेकिन अमेरिका में नए साल के पहले ही दिन हुए आतंकी ट्रक अटैक में 15 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। न्यू ऑरलियन्स में हुए इस कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले ने शांति एवं अमनचैन के दुनिया के मनसूंबों पर पानी फेर दिया। न्यू ऑरलियन्स में हुए इस आतंकी हमले को 42 वर्षीय अमेरिकी नागरिक शम्सुद्दीन जब्बार ने अंजाम दिया, जिसे इस्लामिक स्टेट-आईएसआईएस समर्थक माना जा रहा है क्योंकि उसकी गाड़ी से इस्लामिक स्टेट (आईएस) से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले हैं। इस हमले की जांच 'आतंकवादी कृत्य' के रूप में कर रहे हैं। जब्बार पुलिस की गोलीबारी में मारा गया।

बात केवल अमेरिका में हुए इस आतंकी हमले की नहीं है। समूची दुनिया युद्ध और शांति, आतंक एवं आनन्द, हिंसा और अहिंसा, भय और अभय के बीच झूलस रही है। दुनिया में कई सत्ताएं युद्धरत हैं, जबकि ज्यादातर लोग शांति चाहते हैं। अजीब अंतर्विरोध एवं विरोधाभास देखने को मिल रहा है। शांति का मतलब सिर्फ़ युद्ध का अभाव नहीं होता, बल्कि एक ऐसा वातावरण होता है जहां गतिशील, मज़बूत, सौहार्दपूर्ण और संपन्न समाज का निर्माण होता है। ऐसे समाजों में मानव क्षमता का अधिकाधिक इस्तेमाल होता है और जीवन शांति एवं सहजीवन के रूप में व्यतीत होता है। विडम्बना देखिये कि ज्यादातर लोग शांति, अमन-चैन चाहते हैं फिर भी युद्ध प्रेमी सत्ताएं व्यापक जन-समर्थन हासिल करती जा रही है।

विश्व में उथल पुथल कई मोर्चों पर चली रहती है जिस पर दुनिया का ध्यान आकर्षित होता रहता है। साथ में ही इसका प्रभाव शेष विश्व पर भी पड़ता है, लेकिन विश्व में शांति के लिए संघर्ष जिस बड़े पैमाने पर हो रहे हैं युद्ध एवं आतंक भी उससे बड़े पैमाने पर पनप रहे हैं। इस समय कम से कम दो लंबे युद्ध चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को तीन साल होने वाले हैं, जबकि गाजा और इस्राइल के युद्ध को भी एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है। संसार लगभग चुपचाप, लाचार यह नरसंहार देख रहा है। युद्ध में केवल बर्बरता, लाशें, आग, मलबा और रॉकेट दिख रहे हैं। लोग बेबस हैं, बच्चे अचंभित हैं, औरतों के साथ बर्बरता हो रही है। फिर भी, इन युद्धों को रोकने की कोई सार्थक एवं प्रभावी पहल नहीं हो रही। क्या संसार ने युद्ध की अनिवार्यता और शांति की असंभावना को स्वीकार कर लिया है?

पूरा विश्व इस बीच दो गुटों में बंट चुका है। कुछ देश शांति का समर्थन कर रहे है तो कुछ मौन होकर युद्ध की अनिवार्यता को स्वीकार रहे हैं। लेकिन युद्ध के मुख्य किरदार एक-दूसरे के अस्तित्व को ही मिटाने की जिद्द में गोला-बारूद दाग रहे हैं। मानो एक-दूसरे का नामोनिशान ही मिटा देंगे, लेकिन इस बीच खुद को बचाने के लिए कुछ लोग बंकरों में छिप रहे हैं तो कुछ मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं। युद्ध किसी का भी हो, जख्म बच्चों, महिलाओं एवं निर्दोषों को ही ज्यादा मिलते हैं। युद्ध दो देशों के बीच भले हो, लेकिन इससे समूचा विश्व आहत है, प्रभावित है। इतने व्यापक विनाश, क्रूरता, हिंसा की संसार अनदेखी कैसे कर रहा है, यह प्रश्न मानव के अस्तित्व एवं अस्मिता से जुड़ा होकर भी इतना सून कैसे हैं?

वैसे युद्ध एवं आतंकवाद किसी भी देश के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होता है क्योंकि उसमें जीत-हार तो बाद की बात है, पहले इसमें मानवता को हानि और क्षति होती है। इसलिए युद्ध एवं आतंक न केवल मृत्यु और विनाश का कारण बनते हैं, बल्कि स्थायी शारीरिक और मानसिक विक्षिप्तता का कारण बनते हैं, विकास का अवरोध होता है, पर्यावरण-विनाश का कारण होता है। इक्कीसवीं सदी अपनी निष्ठुरता, अमानवीयता एवं क्रूरता में इतना बेमिसाल और अभूतपूर्व होगी, ऐसी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। शांति की तलाश में लगी दुनिया के लिये युद्ध इतने अनिवार्य कैसे हो गये, यह एक गंभीर प्रश्न है।

पृथ्वी पर जीवन अनमोल और अद्वितीय है। तार्किक रूप से, हम अपनी सभ्यता की प्रगति के ऐसे चरण में हैं कि हमें युद्धों के निहितार्थों को जानना चाहिए और उन्हें होने ही नहीं देना चाहिए। युद्धों में कोई वास्तविक विजेता नहीं होता है क्योंकि इसमें शामिल सभी पक्षों को परिणाम भुगतना पड़ता है जिसमें अक्सर दोनों पक्षों के हताहतों की संख्या अधिक होती है। यह समय मानवता के दुष्काल एवं आपातकाल का समय है, जिसमें युद्धरत होते देशों को मानवीय मूल्यों से हाथ धोना पड़ता है। उन देशों की तो क्षति होती ही है, इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है, चाहे वह आर्थिक तौर पर हो, राजनीतिक, सामाजिक या नैतिक तौर पर हो, युद्धों से होने वाली क्षति की कभी भी भरपाई नहीं हो पाती। सारे संसार में जिस तरह लोकतंत्र का हरण और पूंजीवाद का उत्कर्ष हो रहा है, उसमें शांति के लिए प्रयास धुंधले पड़ रहे हैं। युद्ध चाहे कोई भी हो, कौनसा भी हो, लेकिन वह कभी भी किसी भी देश की लोकतांत्रिक राजनीति, समाजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होता। एक युद्ध जिन देशों के बीच में छिड़ता है, केवल उनकी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की शांति भंग करता है, इसका उदाहरण यूक्रेन-रूस तथा इजरायल-हमास युद्ध के परिणामों से विश्व मानवता पर पड़ रहे दुष्प्रभाव से आंकना होगा। यह जंग सिर्फ अब रॉकेट और मिसाइल के दम पर नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि यह जंग साइबर वर्ल्ड में भी पहुंच चुकी है, जो अधिक घातक है।

यह कोई पहला मौका नहीं है, जब कोई जंग असल दुनिया से लेकर साइबर वर्ल्ड तक पहुंची हो। यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी हमने साइबर अटैक के कई मामले देखे हैं। ऐसा ही कुछ हमास और इजरायल के बीच होता दिख रहा है। हाल में हमास ने इजरायल पर अचानक हमला किया। इस हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। इनमें सैनिकों से लेकर आम आदमी तक सभी शामिल हैं। उनके ऊपर कई साइबर अटैक हुए हैं। फोन ऐप को टार्गेट किया गया। इसके अलावा कई दूसरे मामले भी देखने को मिले हैं। इजरायल का रेड अलर्ट फोन ऐप सिस्टम भी साइबर अटैक का शिकार हुआ है। इस ऐप की मदद से इजरायल में रॉकेट और मिसाइल हमले के वक्त रियल टाइम अलर्ट मिलता है। ये चीजें बताती हैं कि जंग का अंजाम कितना घातक होता है।

अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ गया है कि यूक्रेन को इतने लंबे समय से झुकता न देख रूस का अहं चोट खा रहा है। हालांकि परमाणु हथियारों के दुष्परिणामों से दोनों देश अनजान नहीं हैं। इस तरह युद्धरत बने रहना खुद में एक असाधारण और अति-संवेदनशील मामला है, जो समूची दुनिया को विनाश एवं विध्वंस की ओर धकेलने जैसा है। ऐसे युद्ध का होना विजेता एवं विजित दोनों ही राष्ट्रों को सदियों तक पीछे धकेल देगा, इससे भौतिक हानि के अतिरिक्त मानवता के अपाहिज और विकलांग होने का भी बड़ा कारण बनेगा। इसलिये दुनिया अब युद्ध का अंधेरा नहीं, शांति का उजाला चाहती है। दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य का उजाला करना होगा, जिसमें मानवीय संबंध, संवाद, सहकार, टीवी चैनल, सिनेमा, त्योहार, साहित्य, कलाएं- सभी शांति की विधाएं बनने लगे। नववर्ष में इसकी सार्थक शुरुआत हो एवं नये शांति के सूरज का अभ्युदय हो।

## आज का इतिहास

1889 हर्मन होलैरिथ को पंच कार्ड टैब्युलेटिंग मशीन के आविष्कार का पेटेंट मिला।

1904 ब्लैकस्टोन लाइब्रेरी, शिकागो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम की पहली शाखा समर्पित थी।

1920 1919 की स्टील स्ट्राइक, प्रथम विश्व युद्ध के मद्देनजर संयुक्त राज्य के इस्पात उद्योग को संगठित करने का एक प्रयास, अम्लागमेटेड एसोसिएशन ऑफ आयरन एंड स्टील वर्कर्स के लिए पूरी तरह से विफल हो गया।

1929 नीदरलैंड्स और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेलीफोन संपर्क स्थापित हुआ।

1940 ब्रिटिश सरकार ने मक्खन, बेकन, हैम और चीनी के लिए राशन कार्ड की शुरुआत की।

1952 पश्चिमी जर्मनी की सीमाओं के भीतर 8 मिलियन शरणार्थी पाए गए।

1956 संयुक्त राज्य अमेरिका के पांच इवांजेलिकल ईसाई मिशनरियों को उनके साथ संपर्क बनाने के तुरंत बाद इक्वाडोर के वर्षावन में हुआओरानी द्वारा मार दिया गया था।

1958 14-वर्षीय बॉबी फिशर ने संयुक्त राज्य अमेरिका शतरंज चैम्पियनशिप जीती।

1961 अल्जीरिया की स्वाधीनता को लेकर फ्रांस में जनमत संग्रह कराया गया। जिसमें अल्जीरिया में पक्ष में केवल 69 प्रतिशत मतदान हुआ।

1964 अपने राज्य के संबोधन के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन ने गरीबी पर युद्ध की घोषणा की।

1968 अमरीका में कालों के संघर्ष के नेता मार्टिन लूथर किंग को अज्ञात आक्रमणकारियों ने गोली मार दी जिससे उनकी मृत्यु हो गयी।

1973 रूस का स्पेस मिशन ल्यूना 21 लांच किया।

1977 अर्मेनियाई राष्ट्रवादियों के लिए जिम्मेदार तीन बमों ने मास्को में विस्फोट किया, जिसमें 37 लोग मारे गए।

1979 तेल टैंकर बेतेल्यूज ने आयरलैंड के बैंट्री बे के व्हिडी आईलैंड ऑयल टर्मिनल के अपतटीय जेट्टी में विस्फोट किया, जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए।

1991 लोटारियो डे कोंटी को पोप इनोसेंट ढ्ढढ्ढ के रूप में चुने जाने के बाद, उनका पहला कार्य रोम में पोप शक्ति की बहाली था।

1994 टीएम -18, रूसी मानवयुक्त अंतरिक्ष यान को कक्षा में लॉन्च किया गया है।

1995 मार्टिन बेक थिएटर न्यूयॉर्क शहर में 1143 प्रदर्शन देने के बाद दोस्तों और गुड़िया बंद हो जाता है।

# भारत के सामने 2025 में है अनिश्चितता भरी दुनिया

**अजय छिब्बर**

भारत के लिए 2025 की शुरुआत कुछ दुख भरी रही क्योंकि पिछले साल के अंत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। सिंह वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कर देश को तेज वृद्धि की राह पर ले जाने में मदद की। इस समय अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ रही है और वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर घटकर 5.4 फीसदी ही रह गई। बीते तीन सालों में इसका प्रदर्शन अनुमान से बेहतर रहा है। वित्त वर्ष 22 में यह 8.7 फीसदी, वित्त वर्ष 23 में 7.2 फीसदी और वित्त वर्ष 24 में 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी। इस वृद्धि में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में निवेश और बढ़ते सेवा निर्यात की अहम भूमिका रही।

सरकारी विशेषज्ञों और विश्लेषकों को लगता है कि पिछली तिमाही में वृद्धि में आई गिरावट अस्थायी है। यह तो जल्दी पता चल जाएगा लेकिन कुछ भी हो, देश में निजी निवश ज्यादा नहीं बढ़ रहा और जीसीसी में निवेश अपने चरम पर पहुंच चुका है, इसलिए भारत में वृद्धि कमजोर ही पड़ेगी। इसे मजबूत करना है तो लंबे अरसे से अटके दूसरी पीढ़ी के सुधार जल्द ही करने होंगे।

चिंता की बात यह भी है कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ रही है। अपने हालिया वैश्विक आर्थिक अनुमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2024 से 2029 के दौरान वैश्विक वार्षिक वृद्धि दर 3.1 फीसदी ही रहने की बात कही है। 2000 से 2019 के दौरान यह 3.7 फीसदी थी, जबकि उस बीच वैश्विक वित्तीय संकट भी आया था। अनुमान में वृद्धि दर और भी घटने की चेतावनी दी गई है।

वृद्धि को और धीमा करने वाले चार जोखिम बताए गए हैं- संघर्षों में इजाफा, शुल्क और व्यापार नीति पर अनिश्चितता, कम प्रवासन और बिगड़ते वैश्विक वित्तीय हालात। चारों मिलकर वृद्धि में 1.5 फीसदी कमी ला सकते हैं। पहले दो जोखिम यानी संघर्ष और व्यापार नीति से वैश्विक वृद्धि में आधा-आधा फीसदी कमी हो सकती है तथा बाकी दोनों यानी कम प्रवासन और वित्तीय तंगी से चौथाई-चौथाई फीसदी सुस्ती आ सकती है। पहला जोखिम यानी संघर्ष बढ़ना शायद घटित ही नहीं हो मगर दूसरा यानी शुल्क दर और तीसरा यानी कम प्रवासन लगभग पक्के हैं और इनसे वैश्विक वृद्धि में 1 फीसदी तक कमी आ सकती है। बढ़ती व्यापार और राजकोषीय अनिश्चितता के साथ अमेरिकी फेडरल रिजर्व संकेत दे ही चुका है कि वह ब्याज दर में कटौती की रफ्तार घटाएगा यानी वित्तीय स्थिति पहले ही तंग हो रही है।

कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध हुआ तो चीन प्लस वन नीति के तहत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ सकता है। मगर आईफोन को छोड़ दें तो ज्यादा निवेश चीन से हटकर भारत नहीं आया है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के तहत सब्सिडी होने के बाद भी भारत की लालफीताशाही, श्रम और भूमि कानून तथा द्विपक्षीय निवेश संधियों पर इसके रवैये से निवेश जुटना मुश्किल है। इसके अलावा आईफोन और औषध उत्पाद बनाने के लिए चीन के कच्चे माल पर निर्भरता के कारण अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से भारत को ज्यादा फायदा नहीं मिल सकता।

कुछ विशेषज्ञों की राय है कि भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) या प्रशांत-पार साझेदारी पर व्यापक और प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए। लेकिन चीन से होने वाले आयात पर शुल्क लगाने के बाद भी उस देश के साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत अधिक है और आरसेप में शामिल होने से निकट भविष्य में घाटा और भी बढ़ जाएगा। चीन ने भी सीपीटीपीपी की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता अभी अटका हुआ है, जिसमें यूरोपीय संघ के कार्बन कर के प्रस्ताव ने और भी अड़ंगा लगा दिया है। यूरोपीय संघ के और भी बड़े बाजार के साथ

बातचीत इससे भी ज्यादा जटिल है।

भारत हर सूरत में डॉनल्ड ट्रंप की शुल्क वाली सूची में होगा। वह पहले ही भारत को 'टैरिफ किंग' बता चुके हैं और जवाबी शुल्क लगाने की धमकी भी दी है। भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और ट्रंप के पिछले कार्यकाल की तरह शुल्क की जंग में फंसने के बजाय इस देश के साथ व्यापार तथा निवेश संधि पर आगे बढ़कर बात करना समझदारी होगी। भारत-अमेरिका व्यापार बढ़ाते हुए द्विपक्षीय व्यापार घाटे को कम करना ही लक्ष्य होना चाहिए। दोनों देशों के बीच व्यापार 2030 तक बढ़कर सालाना 500-600 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय बाजारों में पेट्रोलियम, तेल उत्पाद, एलएनजी, परमाणु एवं ऊर्जा उपकरण तथा रक्षा जैसे चुनिंदा अमेरिकी आयात की इजाजत देकर यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

प्रवासन की बात करें तो ट्रंप एच1-बी वीजा और ग्रीन कार्ड के जरिये वैध प्रवासन के हिमायती लगते हैं। बहरहाल करीब आठ लाख भारतीय बिना दस्तावेजों के अमेरिका में रहते हैं। अगर उन्हें वापस भेजने के लिए बड़ा अभियान चला तो भारत पर बहुत असर पड़ेगा।

धीमी वृद्धि ही इकलौती चिंता नहीं है। चालू खाते का घाटा कम होने के बावजूद रुपया कमजोर हो रहा है क्योंकि धन भारत से बाहर जा रहा है। माना जा रहा है कि फेड 2025 में ब्याज दर कटौती धीमी कर देगा, जिसके कारण विदेशी फंड तेजी से धन निकाल रहे हैं। रुपये में लगातार कमी आ रही है और डॉलर के मुकाबले अब वह 86 पर पहुंचने वाला है। इससे भारतीय व्यापार की होड़ करने की क्षमता बढ़ेगी मगर कीमत भी बढ़ेंगी और असुरक्षित ॠण जोखिम में पड़ जाएगा। राजकोषीय नीति के समक्ष कठिन विकल्प हैं। सार्वजनिक ॠण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 83 फीसदी पर पहुंच चुका है और चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.9 फीसदी के बराबर रह सकता है। खजाने को मजबूत करने की राह पर सीधे चला गया तो 2025-26 में राजकोषीय घाटा घटकर जीडीपी के 4.2 फीसदी पर रह जाएगा। मगर 2014 में राष्ट्रीय जतांत्रिक गठबंधन सरकार आने के बाद से किसी वर्ष के घाटे से यह आंकड़ा ज्यादा ही होगा।

बहरहाल अर्द्धवार्षिक समीक्षा में तो यह घाटा जीडीपी के 4.5 फीसदी से कम रहने का वादा किया गया है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बरकरार रखते हुए खजाने को और भी तेजी से मजबूत करने का एक ही रास्ता है ङ्क तेजी से निजीकरण, जो अभी तक बहुत धीमा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक कह चुका है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत बनाने और उसकी गुणवत्ता सुधारने की जरूरत है।

निजी निवेश में सुस्ती पहेली बनी हुई है। 2024 के आरंभ में चुनावी अनिश्चितता को इसकी वजह मान लिया गया था मगर अब अर्थव्यवस्था के एक ही हिस्से में सुधार की वजह से मांग में आई कमी को ही इसकी वजह बताया जा सकता है। इस समय केवल 75 फीसदी क्षमता का इस्तेमाल हो रहा है और बढ़ते आयात के कारण नए निवेश का ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है।

भारत को अधिक समावेशी वृद्धि मॉडल और दूसरी पीढ़ी के सुधारों की जरूरत है। श्रम एवं भूमि अधिग्रहण कानून आसान बनाने और लालफीताशाही कम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग किया जाए तो श्रम के अधिक इस्तेमाल वाले विनिर्माण में निवेश आसानी से बढ़ जाएगा, जो जरूरी भी है। वस्तु एवं सेवा कर जैसे कदमों के लिए भारत को 'सहकारी संघवाद' की जरूरत पड़ती है मगर श्रम तथा भूमि सुधार जैसे क्षेत्रों के लिए और लालफीताशाही खत्म करने के लिए 'प्रतिस्पर्द्धी संघवाद' जरूरी है, जहां प्रगतिशील राज्य रास्ता दिखा सकते हैं। लाखों रोजगार तैयार करने और निवेश आकर्षित करने की क्षमता वाले पर्यटन पर बल देने की जरूरत है। अब चुनाव हो चुके हैं तो आगामी बजट में इस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर है।

रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 25 के लिए वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.7 फीसदी कर दिया है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 6.5 फीसदी का अनुमान लगाया है। पिछले तीन सालों में औसतन 8 फीसदी से ऊपर की शानदार वृद्धि होने के बाद भी देश का जीडीपी उस स्तर से नीचे ही रहेगा, जहां वह महामारी नहीं आने पर होता। वैश्विक हालात बिगड़ने और ट्रंप के व्यापार तथा प्रवासन झटकों से वृद्धि दर घटकर 6 से 6.5 फीसदी रह सकती है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। अगर भारत दोबारा 7.5 से 8 फीसदी की ज्यादा समावेशी वृद्धि चाहता है तो अभी तक अटके दूसरी पीढ़ी के सुधारों को अंजाम देना होगा। देखते हैं कि भारत ऐसा कर विकसित भारत के उस रास्ते पर चलता रहता है या नहीं, जिसकी शुरुआत मनमोहन सिंह ने 1991 में उदारीकरण के साथ की थी।

# क्या चीन फिर दुनिया में महामारी फैलाएगा?

**अभिषेक कुमार सिंह**

अभी इस घटना को आधा दशक ही बीता है, जब सर्दियों के दौरान चीन से एक वैश्विक आपदा ने कोरोना वायरस की शक्ल में जन्म लिया था। एक बार फिर वहां से एक नये वायरस की आमद ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। भारत में भी इसके कुछ मामले सामने आए हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी से पर्याप्त सबक ले चुकी दुनिया इस बार कहीं ज्यादा सतर्क है और उत्तरी चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस (एचएमपीवी) नाम के इस नये वायरस के संक्रमण से निपटने को तैयार है। लेकिन सर्दी-जुकाम और कोविड-19 जैसे ही लक्षणों वाली इस संक्रामक बीमारी ने कई सवाल हमारे सामने उपस्थित कर दिए हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इतनी अधिक तरक्की के बावजूद हमारा चिकित्सा विज्ञान नये संक्रमणों की पैदावार को क्यों नहीं रोक पा रहा है। कोई भी नया और तेजी से फैलने वाला संक्रमण हमारी चिंताओं का सबब इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी कोविड-19 के घाव भरे नहीं हैं। कोरोना काल में जिस तरह दुनिया भर में करोड़ों लोग संक्रमित हुए, लाखों मौतें हुईं, अनगिनत नौकरियां चली गईं और असंख्य काम-धंधे ठप हो गए और अर्थव्यवस्थाएं ढह गईं- उन्हें देखकर नये वायरस की सूचना पर दुनिया का चौंक पड़ना स्वाभाविक ही लगता है। तथ्यों को देखें तो चीन के जिन कुछ हिस्सों में इस वायरस के उभार के मामले देखे गए हैं, वहां लोगों में इसके कारण सर्दी-जुकाम और कोविड-19 जैसे लक्षण नजर आए हैं और वहां तेजी से इसकी चपेट में आने वालों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि चीनी सरकार और वहां के स्वास्थ्य तंत्र का दावा है कि सर्दियों में फ्लू और इसके जैसे लक्षणों वाले संक्रमण का फैलना असामान्य नहीं है। लेकिन जिस तरह से चीन के सरकारी मीडिया संगठन-ग्लोबल टाइम्स ने यह जानकारी प्रकाशित की है कि उत्तरी चीन के अलावा बीजिंग, दक्षिण पश्चिमी शहर चोंगकिंग, दक्षिणी चीन के गुआंगदोंग प्रांत में एचएमपीवी के मामले पकड़ में आए हैं, उससे लगता है कि हालात सामान्य नहीं हैं। खुद चीन की स्वास्थ्य एजेंसियों ने नये वायरस की आहट के साथ पायलट सर्विलांस सिस्टम शुरू किया है, जो स्थितियों का चिंताजनक हो जाना साबित कर रहा है। यह सर्विलांस सिस्टम अज्ञात कारणों से होने वाले निमोनिया के मामलों की खास तौर से जांच कर रहा है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चीन सरकार से हालात के बारे में समय-समय पर जानकारी साझा करने की मांग की है। इससे लगता है कि खुद चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह आशंका सता रही है कि कहीं हालात बेकाबू न हो जाएं। चीन के लिए चिंता यह है कि जिस तरह वुहान के बाजार से कोराना वायरस की उत्पत्ति के कारण उसे दुनिया भर की तोहमतें झेलनी पड़ी थीं (हालांकि चीन ने इसे तथ्यात्मक रूप से स्वीकार नहीं किया कि वह कोरोना का उत्सर्जक देश है), कहीं इस बार भी उसे कठघरे में न ले लिया जाए कि एक नये वायरस की रोकथाम वह नहीं कर पाया। उल्लेखनीय है कि वायरसों के उद्भव, उनके प्रसार और दुनिया से संबंधित जानकारियों को छिपाने के इतिहास को देखते हुए चीन के दावों और आश्वासनों पर कम ही यकीन किया जाता है।

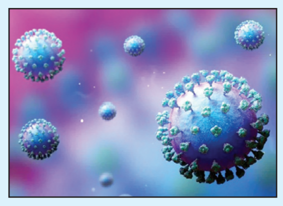

# पांच साल में कितनी बदली दिल्ली की सियासत ?

**शिवेंद्र तिवारी**

दिल्ली में मंगलवार को विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान हो गया है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला तीन पार्टी- आम आदमी पार्टी (आप), कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। जहां आम आदमी पार्टी अपनी 12 साल की सत्ता को बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस शीला दीक्षित के शासन में कायम की गई अपनी साख को वापस हासिल करने पर केंद्रित है। इन सबके बीच भाजपा कई वर्षों बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के रास्ते तलाश रही है।

चुनाव से पहले आप, विपक्षी भाजपा और कांग्रेस ने अपनी-अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। तीनों ही पार्टियों ने अपने कुछ उम्मीदवारों का एलान कर दिया है। आप-भाजपा की लिस्ट में तो दूसरी पार्टी से आए नेताओं को भी मौका दिया गया है। उधर विपक्षी कांग्रेस ने हाल ही में दिल्ली न्याय यात्रा निकाली। वहीं भाजपा ने भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा निकालने से जुड़ा एलान किया था।

पांच साल में दिल्ली कई सियासी उठापटक का गवाह रही है। दो चेहरों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जहां एक ओर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद जेल से सरकार चलाई गई तो दूसरी ओर कुछ मंत्रियों ने दल बदल लिया। अब वो विपक्षी दलों के साथ हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के केंद्र में कथित शराब घोटाला भी रहा। इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंसे हैं। जेल से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी कैबिनेट में मंत्री रहीं आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली।

आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए इसका तीसरा कार्यकाल चुनौतियों भरा रहा। इसके केंद्र में कथित शराब घोटाला रहा। दरअसल, कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी।

इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि, नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया।

आप के लिए मुश्किलें यही तक नहीं थीं और अगस्त 2022 में शराब नीति मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। आप नेताओं समेत 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया था। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी।

अक्तूबर 2022 में आप सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम विवादों में फंस गए जब उन्होंने एक कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। भाजपा नेताओं ने मंत्री के भाषण की आलोचना की और उनके खिलाफ कानूनी शिकायतें कीं। इसके बाद 9 अक्तूबर 2022 को उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त राजेंद्र ने कहा था, %मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे नेता केजरीवाल और मेरी पार्टी को किसी भी तरह का नुकसान हो।% हालांकि, सितंबर 2024 में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और एक प्रमुख दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हो गए।

मई 2022 में ईडी ने दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को मनी-लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। फरवरी 2023 में शराब नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। फरवरी 2023 के अंत में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

कई विभाग संभालने वाले दो मंत्रियों की गिरफ्तारी से आप सरकार संकट में दिखाई देने लगी। इस बीच मार्च 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कैबिनेट विस्तार किया और दो विधायकों सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की जिम्मेदारी थमाई। सौरभ को स्वास्थ्य तो आतिशी को शिक्षा के साथ कई अहम विभागों का भी प्रभार दिया गया। इसके बाद सरकार के कुछ विभागों में फेरबदल किए गए।

अक्तूबर 2023 में दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आप के लिए झटके कम नहीं हुए और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तब बहुत बड़ा झटका लगा जब इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। मार्च 2024 में शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली।

पार्टी नेताओं पर हो रही लगातार कार्रवाई के बीच दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी को अलविदा कह दिया। राजकुमार ने आबकारी नीति घोटाले का विरोध करते हुए अप्रैल 2024 में मंत्री पद और आम आदमी पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। वह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मई 2024 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। हालांकि, जुलाई 2024 में पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।

# नीतीश : साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं

**विजय विद्रोही**

नया साल शुरू हो गया है 2025 में ऐसी कौन सी सियासी घटनाएं हो सकती हैं जिस पर नजर रहेगी। पहली सियासी घटना तो बिहार से जुड़ी है। नीतीश कुमार क्या करेंगे? विधानसभा चुनाव किस गठबंधन में रह कर लड़ेंगे? इसकी कयासबाजी तेज है। कभी भाजपा नेता ही संकेत देते हैं कि नया मुख्यमंत्री चुनावों बाद तय होगा तो कभी खुद ही भाजपा के नेता नीतीश कुमार को वर्तमान और भावी मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं।

कभी लालू का बयान आता है कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं तो कभी तेजस्वी इस साल बिहार में नई सरकार का ट्वीट कर देते हैं। सोशल मीडिया में तो हल्ला है कि नीतीश अब गए तब गए, लेकिन हैरानी की बात है कि नीतीश कुमार खामोश हैं। उनकी खामोशी बहुतों को बेचैन कर रही है। साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं का सियासी खेल वह खेल रहे हैं। दूसरी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव की सुर्खियों में रहने वाली है। नतीजा चाहे जो हो,अरविंद केजरीवाल अगर इस बार भी जीते तो अपनी राजनीति का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने की दिशा में बढ़ेंगे और 'इंडिया' मोर्चे से कांग्रेस को अलग थलग करने पर जोर देते रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव केजरीवाल के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। तीसरी खबर इस साल भी 'इंडिया' बनाम एन.डी.ए. के बीच तकरार रहने वाली है। संसद से लेकर सड़क तक तल्खी बनी रहेगी इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बीच-बीच में 'इंडिया' मोर्चे में टूटन आदि की खबरें भी आती रहेंगी लेकिन कुल मिलाकर मोर्चा जिंदा रहेगा जिसकी असली

अग्नि परीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव में होगी।

इसके अलावा नरेन्द्र मोदी बनाम राहुल गांधी के बीच की अदावत भी साल भर चर्चा में बनी रहेगी। राहुल गांधी अडानी, जातीय जनगणना, संविधान बचाओ जैसे मुद्दों को उठाते रहेंगे और सत्ता पक्ष नेहरू गांधी परिवार को निशाने पर लेता रहेगा। पांचवां मसला जिस पर नजर रहेगी वह आंबेडकर के कथित अपमान से जुड़ा है। विपक्ष इस मसले को साल भर भुनाने की कोशिश करता रहेगा।

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट फरवरी में होगा। पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने कोई बड़ा आर्थिक सुधार नहीं किया है। इस बार माना जा रहा है कि वह कुछ बड़े और कड़े फैसले ले सकते हैं। तीन श्रम कानूनों को क्या इस बार लागू किया जाएगा? क्या कार्पोरेट टैक्स में तबदीली होगी? क्या कृषि कानूनों को बदले हुए स्वरूप में फिर से लागू किया जाएगा? जानकारों का कहना है कि बैसाखियों पर टिकी सरकार के लिए नीतीश-नायडू की सहमति लेना जरूरी होगा। जिस तरह से नायडू के इशारे पर वक्फ बिल संयुक्त समिति को सौंपा गया उससे साफ है कि साथियों को मनाने में मोदी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

इस साल आर्थिक सुस्ती भी सरकार की परीक्षा लेगी। बहुत कुछ अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प के रुख पर निर्भर करेगा, खासतौर से उनकी 50 फीसदी तक टैरिफ लगाने की धमकी और वहां अवैध तरीके से रह रहे सवा 7 लाख भारतीयों का क्या होगा? कुल मिलाकर ट्रम्प और मोदी की दोस्ती भी कसौटी पर रह सकती है। दसवीं खबर भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी हुई है। माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद फरवरी या मार्च में नया अध्यक्ष मिल सकता है। आंबेडकर विवाद के बाद क्या किसी दलित को ताज पहनाया जा सकता है। महिला वोटरों की बढ़ती ताकत को देखते हुए क्या भाजपा को पहला महिला अध्यक्ष मिल सकता है या फिर कोई युवा चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है।

तर्क दिया जा रहा है कि 'इंडिया' मोर्चे में ममता, तेजस्वी, अखिलेश, राहुल, आदित्य ठाकरे, केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला जैसे युवा चेहरे हैं। इनकी काट के लिए भाजपा का नया अध्यक्ष 55 से 60 साल के बीच का कोई हो सकता है। जो होगा वह भागवत की पसंद का होगा या मोदी की या फिर मिली जुली पसंद। देखना दिलचस्प रहेगा। वैसे साल भर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच सियासी मुकाबला भी खबरों का हिस्सा हो सकता है। प्रियंका ने संसद में अपने भाषणों से छाप छोड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन राहुल गांधी ने कभी अभय मुद्रा तो कभी एकलव्य का उदाहरण सामने रखा है। दोनों चर्चा में रहे तो फायदा कांग्रेस को ही होगा। कुछ का कहना है कि इस साल कांग्रेस में प्रियंका का नया मजबूत पावर सैंटर शुरू हो सकता है।

जहां तक अदालतों की बात है तो इस साल राहुल गांधी पर चल रहे केस यूं ही तारीख पे तारीख के बीच चलते रहेंगे या कोई फैसला भी आएगा। उनकी नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। वैसे तो प्रियंका गांधी की वायनाड से सांसदी पर भी मामला अदालत में है। लेकिन जानकारों का कहना है कि भाई-बहन को संसद से निकाल बाहर करने का जोखिम मोदी सरकार नहीं लेगी। अलबत्ता 1991 के उपासना स्थल कानून के बारे में जनवरी में ही मोदी सरकार को अपना रुख सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। यह देखना दिलचस्प रहेगा कि कानून को मोदी सरकार सही ठहराती है या मीन मेख निकालती है या बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश करती है। जाहिर है कि अगर मोदी सरकार ने 1991 के एक्ट को सही बताया तो उग्र हिंदूवादी तत्वों की नाराजगी बढ़ सकती है जो पहले से ही मोहन भागवत के हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं तलाशने की नसीहत से नाराज चल रहे हैं।

इस साल वक्फ बिल के साथ साथ 'एक देश-एक चुनाव' बिल भी संसद में पारित होने के लिए रखे जाएंगे। क्या 'एक देश-एक चुनाव' बिल को दो तिहाई मतों से दोनों सदनों में पारित करवाने में मोदी कामयाब होंगे या बिल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बात संसद की हो रही है तो क्या 2024 की तरह 2025 में भी दोनों सदन उसी तरह चलेंगे। क्या राज्यसभा सभापति के खिलाफ नए सिरे से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा या वह लचीला रुख अपनाते नजर आएंगे। वैसे इस साल सितंबर में मोदी 75 के हो जाएंगे। लेकिन 2029 तक तो वे हैं ही। आगे की रणनीति वो खुद ही तय करेंगे, यह पक्का है।

# ट्रूडो के इस्तीफे का कनाडा भारत के रिश्तों पर क्या असर?

**शुभम कुमार**

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे ने कनाडा की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ट्रूडो इस्तीफे ने कनाडा की राजनीति में गर्माहट है ही लेकिन अब एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ट्रूडो के इस कदम से भारत-कनाडा के रिश्ते पर कैसा असर पड़ने वाला है? इसी बीच तेजी से खड़े हो रहे भारत-कनाडा के रिश्ते को लेकर कनाडाई पत्रकार डैनियल बोर्डमैन ने कहा कि ट्रूडो का इस्तीफा भारत के लिए अच्छा हो सकता है। बता दें कि भारत के साथ अपने देश के संबंधों को तनावपूर्ण बनाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद और लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रूडो ने पार्टी अध्यक्ष से नया नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। नए नेता के चुनाव होने तक वह पीएम बने रहेंगे। कनाडा में अक्तूबर में आम चुनाव होने हैं। भारत-कनाडा संबंधों पर असर पड़ने वाले सवाल के जवाब में कनाडाई पत्रकार डैनियल बोर्डमैन ने कहा कि यह भारत के लिए अच्छा हो सकता है। उन्होंने बताया कि भारत में अपने सीमित अनुभवों के आधार पर उन्हें यह महसूस हुआ कि भारतीयों को कनाडा से कोई समस्या नहीं है, वे कनाडा को पसंद करते हैं। हालांकि, जब ट्रूडो और जगमीत सिंह का नाम आता है, तो भारतीय गुस्से में आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। बोर्डमैन ने भरोसा जताया कि कंजर्वेटिव सरकार के आने के बाद इस स्थिति में सुधार हो सकता है। कनाडाई पत्रकार डैनियल बोर्डमैन के मुताबिक प्रधानमंत्री ट्रूडो के इस्तीफे से कनाडा में लोग खुशी का महौल हैं और यह स्थिति संसद की जांच के बाद स्पष्ट हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि मार्च तक लिबरल पार्टी का नेतृत्व बदल सकता है और कनाडा में गर्मियों में चुनाव होने की संभावना है। साथ ही बोर्डमैन ने यह भी कहा कि ट्रूडो का पिछले आठ सालों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा होना कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में अस्थिरता का कारण बना। भारत-कनाडा के रिश्ते में उथल-पुथल पिछले साल से ही देखने को मिल रही है। चाहे वो खालिस्तानी विवाद हो या आतंकी निज्जर का मामला या फिर हिंदु मंदिरों पर हमला। इन सभी मामलों पर ट्रूडो की भारत विरोधी विचारधारा ने भारत के साथ कनाडा के रिश्ते को खट्टा करने में मुख्य भूमिका निभाई, जिससे दोनों देशों में तनावपूर्ण महौल देखने को मिला। हालांकि अब कयास लगाए जा रहे है कि भारत और कनाडा के रिश्चते अब सुधर सकते है। खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय अफसरों की संलिप्तता का आरोप लगाने से ट्रूडो की छवि खराब हुई। ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से कनाडा में भारतीय राजनयिकों पर जासूसी के झूठे आरोप लगाए, जिससे दोनों देशों के रिश्ते रसातल में पहुंच गए। कनाडा में हाल में हुए सभी सर्वेक्षणों में ट्रूडो लगातार पीछे चल रहे थे। देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के लिए ट्रूडो की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देशवासी लंबे समय से सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहीं, विपक्ष के नेता पियरे पोलिवर लगातार उनपर हमलावर हैं।

हमारी शिक्षा, लाइफ और करियर में क्रिएटिविटी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन यह बात छोटे बच्चे को आप कैसे समझाएं? अब समर वेकेशन शुरू हो चुकी है और ऐसे में पैरेंट्स यही सोचते हैं कि इन छुट्टियों को बच्चों के लिए कैसे प्रोडक्टिव बनाएं।

# बच्चों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के ये हैं बेस्ट तरीके

क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है, जो आपको जीवन में और बेहतर बनाता है। हालांकि यह एक गलत धारणा है कि रचनात्मकता एक जन्मजात प्रतिभा है। इसमें आप खूब सारे आइडियाज और इमेजिनेशन का यूज करते हैं और कुछ शानदार आर्ट के साथ आते हैं। हमारी शिक्षा, लाइफ और करियर में क्रिएटिविटी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन यह बात छोटे बच्चे को आप कैसे समझाएं? अब समर वेकेशन शुरू हो चुकी है और ऐसे में पैरेंट्स यही सोचते हैं कि इन छुट्टियों को बच्चों के लिए कैसे प्रोडक्टिव बनाएं। अपने बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग के लिए कैसे प्रोत्साहित करें यह हर मां-बाप सोचता है।

सीनियर क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट कहती हैं, 'बच्चों को नई चीजों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें उन चीजों के बारे में बताएं और वो चीजें करने के लिए प्रेरित करें, जो उनकी स्कूल करिकुलम का हिस्सा न हों। उनके साथ डॉक्यूमेंट्री देखें और उनसे डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूछें।' आइए एक्सपर्ट से जानें कि बच्चों को और किन तरीकों से प्रेरित किया जा सकता है।

## बच्चों को सवाल पूछना सिखाएं

बच्चों में रचनात्मक सोच विकसित करने का एक मेन तरीका यह है कि उन्हें हमेशा सवाल करते रहने के लिए प्रेरित करें जब भी आप उनके साथ समय बिता रहे हों तो उनसे सवाल पूछें। जैसे आप उनसे छोटे-छोटे सवाल कर सकते हैं। ऐसे में उनके मन में जिज्ञासा बनेगी और वह नई चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इससे उनके कल्पनाशील कौशल में वृद्धि होगी और समस्या को सुलझाने की क्षमता विकसित होगी।

## अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएं

एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री स्टोरी स्टूडेंट्स की लिटरेसी को सोर्स, स्वयं से और दुनिया से जुड़ाव के साथ बढ़ाने में मदद करती है। यह न केवल दुनिया को समझने और उससे जुड़ने का अवसर प्रदान करती हैं, बल्कि हमारे आसपास कई चीजों को समझने का भी एक अच्छा तरीका है। अपने बच्चों के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो उसकी चर्चा करें। उन्होंने इससे क्या सीखा और क्या समझा जानने की कोशिश करें।

## उनके साथ क्विज और पजल खेलें

क्विज और पजल जैसे गेम बच्चों के दिमागी विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। पजल आपके बच्चे की समस्या-समाधान और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को विकसित करती हैं, जो बाद में जीवन में अन्य स्किल की महारत के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। पजल्स बच्चों को पैटर्न रिकग्निशन, मेमोरी और ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल दोनों में मदद कर सकती हैं। इसलिए उनके साथ पजल खेलें।

## आउटडोर गेम खिलाएं

अपने बच्चों को घर में रहने के लिए ही न कहें। उन्हें बाहर निकालें और कई फन एक्टिविटीज में उन्हें शामिल होने के लिए कहें। बच्चों के साथ आउटडोर गेम्स खेलें। ऐसे में उनकी एक्सरसाइज भी होगी और वे कुछ नया भी सीखेंगे। आप उन्हें तैराकी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। किसी गेम में जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि जैसे खेलों में शामिल होने के लिए कह सकते हैं।

## सामाजिक और भावनात्मक कौशल सिखाएं

अपने बच्चों सामाजिक और भावनात्मक कौशल सिखाना भी बहुत जरूरी है। उन्हें पशु आश्रयों और वृद्धाश्रमों जैसी जगहों पर ले जाएं और स्वयं सेवा का महत्व सिखाएं। जब बच्चे ऐसा करेंगे तो वह औरों के प्रति भी सेंसेटिव अप्रोच रखने में सक्षम होंगे। ऐसी जगहों पर वे महत्वपूर्ण सामाजिक और भावनात्मक कौशल सीख सकेंगे और साथ ही समाज में भी योगदान दे सकेंगे।

## नींद में न करें लापरवाही

इन सबके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका बच्चा पूरी और अच्छी नींद ले। अच्छी नींद का मतलब है कि उसके दिमाग को बेहतर आइडियाज उत्पन्न करने के लिए और नई चीजों पर काम करने के लिए समय मिलेगा। इनोवेटिव आइडियाज तभी आएंगे जब उसके दिमाग को शांति मिलेगी। बाकी एक्टिविटी के साथ उसकी नींद का भी पूरा ध्यान दें।

# घर में लगाएं ये फूल तनाव होगा दूर, भीनी-भीनी खुशबू से आएंगी जीवन में खुशियां

आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में सुकुन के दो पल चुराना बेहद मुश्किल हो गया है। बिजी लाइफ स्टाइल की वजह से लोग अक्सर तनाव में रहते हैं। ऐसे में इस तनाव को दूर करने के लिए अधिकतर लोग शहर से दूर बाहर किसी हिल स्टेशन पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन हर कोई टेंशन कम करने के लिए हिल स्टेशन नही जा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तनाव में रहें।

आप जीवन की टेंशन को घर में ही कम कर सकते हैं। आपके दिमाग में भी यही सवाल आया होगा कि कैसे टेंशन कम होगी? घबराइए मत हम आपकी सारी उलझन को दूर कर देंगे। इस लेख में हम आपको कुछ फूल के बारे में बताएंगे, जो आपके घर में खुशियां लेकर आएंगे। साथ ही यह फूल घर के साथ-साथ जीवन को भी महका देंगे।

## चमेली

फूल न केवल घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। ऐसे में आप अपने घर में चमेली के फूल का पौधा लगा सकते हैं। चमेली का फूल अक्सर हर घर में मिल जाता है। इस फूल से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। फूल की भीनी-भीनी खुशबू आपके घर को खुशनुमा माहौल देगी। कहा जाता है कि चमेली का पौधा लगाने से घर में खुशियां आती हैं।

## कमल

हिंदू धर्म में कमल का फूल बेहद खास माना जाता है। यह फूल मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। कहा जाता है कि इस फूल को लगाने से घर में लक्ष्मी और सुख-समृद्धि आती है। घर में इस पौधे को लगाना बेहद शुभ माना जाता है।

## मोगरा का फूल

ऐसा कहा जाता है कि घर में मोगरा पौधा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। मोगरे के फूल गर्मियों के मौसम में खिलता है। इस फूल की भीनी-भीनी खुशबू आपके तनाव को कम कर देंगे। मोगरा के फूल की खुशबू से घर आपके मन को तरोताजा कर देगी।

## गुलाब

गुलाब का फूल न केवल दिखने में खूबसूरत है बल्कि यह फूल औषधीय गुण से भरपूर है। गुलाब की खुशबू तनाव को दूर करने में मदद करती है, साथ ही इससे रिश्ते की मिठास बनी रहती हैं।

## चम्पा

चम्पा फूल को लगाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। हल्के पीले और सफेद रंग के ये चम्पा के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इस फूल को लगाने से घर में सौभाग्य आता है।

## गुड़हल का फूल

गुड़हल के फूल का उपयोग पूजा-पाठ में किया जाता है। भगवान गणेश को लाल गुड़हल के फूल बेहद पसंद है। ऐसा माना जाता है कि इस फूल को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। लाल गुड़हल के फूल को आप भगवान बजरंगबली को भी अर्पित कर सकते हैं।

## पारिजात

ऐसा माना जाता है कि पारिजात का फूल लगाने से घर में सुख-शांति बनी रहती है। यह फूल रात के समय में खिलते हैं सुबह पेड़ से टूटकर गिर जाते हैं। इस फूल की खुशबू से पूरा घर महक जाता है। सुबह-सुबह घर में भीनी-भीनी खुशबू से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती हैं। पारिजात के फूल को हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। इस फूल की खुशबू से तनाव कम हो जाता है।

फर्नीचर हर घर की जरूरत है। आमतौर पर, लोग अपने घर के लिए ऐसे फर्नीचर खरीदना पसंद करते हैं, जो देखने में आकर्षक भी हों और बेहद अफोर्डेबल भी हों। इस लिहाज से प्लास्टिक के फर्नीचर का चयन करना एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इनमें आपको डिजाइन से लेकर साइज व कलर आदि में एक बिग वैरायटी देखने को मिलेगी।

# घर में प्लास्टिक फर्नीचर रखते समय वास्तु के इन टिप्स का रखें ध्यान

यूं तो प्लास्टिक के फर्नीचर का इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक के फर्नीचर को घर में जगह दे रही हैं, तो आपको वास्तु के कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल, प्लास्टिक के फर्नीचर को अगर घर में सही तरह से ना रखा जाए तो यह कभी-कभी नकारात्मकता भी पैदा कर सकते हैं। तो चलिए आज इस लेख में आपको वास्तुशास्त्री डॉ. आनंद भारद्वाज बता रहे हैं कि घर में प्लास्टिक के फर्नीचर रखते समय किन वास्तु टिप्स का ख्याल रखा जाना चाहिए

## कलर का रखें ख्याल

जब आप प्लास्टिक के फर्नीचर का इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उस फर्नीचर का कलर कैसा है। आमतौर पर, प्लास्टिक के फर्नीचर के लिए क्रीम, व्हाइट, येलो और लाइट कलर का इस्तेमाल करना काफी अच्छा माना जाता है। कभी भी ब्लैक कलर के प्लास्टिक फर्नीचर को घर में नहीं रखना चाहिए। वहीं, आजकल ऐसे प्लास्टिक फर्नीचर भी अवेलेबल हैं, जिसमें एक साथ कई कलर मिक्स होते हैं, बेहतर होगा कि आप उसे भी अवॉयड करें।

## जब करें स्टडी

आजकल बच्चों की स्टडी टेबल और चेयर प्लास्टिक की मिलती हैं, जिन्हें लोग खरीदना काफी पसंद करते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार बच्चों की स्टडी टेबल और चेयर प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चे को पढ़ाई में ध्यान लगाने में समस्या पैदा हो सकती है। बेहतर होगा कि आप उनके लिए लकड़ी से बने फर्नीचर को प्राथमिकता दें। हालांकि, आप किसी कारणवश प्लास्टिक फर्नीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर कोई कपड़ा बिछा दें।

## जब करें पूजा

ऐसे कई लोग होते हैं, जिन्हें घुटनों की समस्या होती है तो वह कुर्सी पर बैठकर पूजा करते हैं। कोशिश करें कि आप जिस कुर्सी का इस्तेमाल पूजा स्थान में कर रहे हैं,, वह प्लास्टिक की ना हो। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो कुर्सी पर कोई कपड़ा अवश्य बिछाएं। आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पूजा करते समय आप प्लास्टिक के डायरेक्ट संपर्क में ना रहें।

## लॉन में करें इस्तेमाल

यूं तो प्लास्टिक के फर्नीचर को लोग घर के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आमतौर पर इस तरह के फर्नीचर को ऐसी जगह रखने की सलाह दी जाती है, जहां पर आप फुर्सत के पल बिताते हों और कोई बहुत आवश्यक या सेंसेटिव काम ना करते हों। इस लिहाज से प्लास्टिक फर्नीचर को घर के पीछे लॉन या फिर सामने खुले आंगन, व छत आदि पर रखना अधिक अच्छा माना जाता है।

## प्लास्टिक का ना हो बेड

कुछ समय पहले तक बेड बनाते समय केवल लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब मार्केट में प्लास्टिक के बेड भी मिलने लगे हैं। हालांकि, कभी भी घर में प्लास्टिक के बेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेड एक ऐसा फर्नीचर है, जिस पर आप एक लंबा समय बिताते हैं। ऐसे में प्लास्टिक की एनर्जी आपकी बॉडी की एनर्जी में नकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। बेड के लिए हमेशा लकड़ी के इस्तेमाल को ही प्राथमिकता दें।

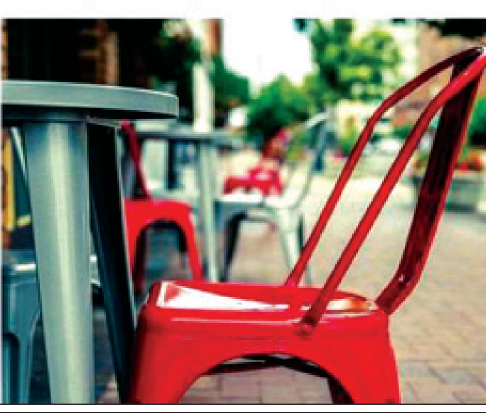

# 1 नहीं बल्कि 3 तरीकों से उगाया जा सकता है फ्रेश हरा धनिया

भारतीय घरों में खाने का जायका बढ़ाने के लिए हरा धनिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हर रसोई में खाने में स्वाद और फ्लेवर के लिए फ्रेश धनिया गार्निश के लिए डाला जाता है। हालांकि, हर वक्त फ्रेश धनिया लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप घर में ही फ्रेश धनिया उगा सकती हैं और वो भी 3 तरीकों से। जी हां, आपने सही पढ़ क्योंकि आज आप इस लेख में जानने वाले हैं घर पर आसानी से हरा धनिया कैसे उगाया जा सकता है

## सीड्स से उगाएं हरा धनिया

आप अपने गार्डन में हरा धनिया बीज की सहायता से लगा सकती हैं।( सेहत के लिए वरदान है हरा धनिया, डाइट में जरूर करें शामिल) आपको किसी भी प्लांट की शॉप से बीज आसानी से मिल जाएंगे, जिसे आप किसी गमले, कंटेनर या फिर प्लास्टिक की बोतल में मिट्टी की मदद से पौधा लगा सकती हैं। हालांकि, पौधे की ग्रोथ तभी होगी जब आप इसका नियमित रूप से ध्यान रखेंगी जैसे- आप मिट्टी की नमी पर ध्यान दें, पौधे में नियमित रूप से पानी डालें।

## कटिंग से उगाएं हरा धनिया

आप अपने किचन में भी हरा धनिया का पौधा लगा सकती हैं। इसके लिए, आपको बस धनिये के पत्ते की जरूरत होगी। हालांकि, इसके पौधे को सही तरीके से लगाने के लिए आपको मिट्टी सही तरीके से तैयार करनी होगी। साथ ही, आपको बाजार से गमला खरीदकर लाना होगा और इसमें मिट्टी और खाद की मदद से कटिंग लगानी होगी।

## हरा धनिया की जड़ का करें इस्तेमाल

बहुत-सी महिलाएं हरा धनिये की जड़ को बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप इसकी जड़ की सहायता से फ्रेश हरा धनिया भी उगा सकती हैं। कहा जाता है कि जड़ से उगाया गया पौधा बीज से ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती हैं। इसके लिए बस आपको मिट्टी में जड़ को बोना है और नियमित तौर पर पानी डालना है।

## धनिया उगाने का आसान तरीका

**आवश्यक सामग्री-** कंटेनर/गमला/ प्लास्टिक की बोतल, मिट्टी और खाद, कटिंग/बीज, पानी

विधि - पौधा लगाने के लिए सबसे पहले आपको गमले का चुनाव करना होगा। आप छोटा गमला सेलेक्ट कर सकती हैं। गमले का चुनाव करने के बाद आप इसमें मिट्टी डालें और अच्छी तरह से मिला लें। आप पौधे की मिट्टी तैयार करते समय 50% कोको-पीट और 50% वर्मीकम्पोस्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं।

मिट्टी तैयार करने के बाद आप इसमें पौधे की कटिंग, बीज को अच्छी तरह से लगा दें। कटिंग या बीज को लगाने के बाद आप पौधे में पानी डालें।

बस आपका पौधा पूरी तरह से तैयार है। आप इसका नियमित रूप से ध्यान रखें और फ्रेश हरा धनिया आने का इंतजार करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

## वीरेंद्र सचदेवा का संजय सिंह और राघव चड्ढा पर निशाना

**नईदिल्ली।** भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग उस तारीख का भी इंतजार कर रहे हैं जिस दिन वे इस आपदा सरकार से मुक्त होंगे। दिल्ली सरकार द्वारा की गई लूट को अलविदा कहने का समय आ गया है। आप को लेकर डीईओ की चिट्ठी पर बीजेपी नेता ने कहा कि हम पिछले 3 महीने से यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। भाजपा नेता ने कहा कि सार्वजनिक अवकाश के दिन राघव चड्ढा और संजय सिंह ने चुनाव अधिकारियों को धमकाया। इससे पता चलता है कि वे पूरी तरह से अपनी जमीन खो चुके हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आप हर संवैधानिक संस्था को धमकी देती है। उनका शहरी नक्सली स्वभाव हमेशा बना रहता है।

## दिल्ली चुनाव के लिए आप का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च

**नईदिल्ली।** आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार गीत जारी किया। फिर लाएंगे केजरीवाल शीर्षक वाला अभियान गीत आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और मनीष सिसोदिया सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में जारी किया गया। चुनाव अगले महीने फरवरी होने वाले हैं और परिणाम भी उसी महीने घोषित किए जाएंगे। दिल्ली में मुख्य मुकाबला आप और भाजपा के बीच माना जा रहा है लेकिन कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। लॉन्च के दौरान आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और देश के लोगों को ये गाना समर्पित कर रहे हैं। शादियों में, बर्थडे में इस गाने को बजाइए। केजरीवाल ने बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से तंज कसा और कहा कि देश में गाली गलौच पार्टी है, उसे भी ये गाना पसंद आएगा। वो कमरे बंद करके सुन सकते हैं। थिरक सकते हैं।

## दिल्ली में आप और भाजपा के खिलाफ लहर : अलका लांबा

**नईदिल्ली।** चुनाव आयोग आगामी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दिया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता विरोधी लहर है। उन्होंने कहा कि लोगों ने एक दशक तक शासन देखा है और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और उनके बाद आए अन्य लोगों के तहत किए गए कार्यों की तुलना की है। लांबा ने कहा, लोग इस बार कांग्रेस को वोट देंगे। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार लांबा ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। लोग अलग-अलग सरकारों के कामों की तुलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल तक शीला दीक्षित शासन कर रही थीं। केजरीवाल को तीन बार मौका मिला। लोगों ने इस शासन के 10 वर्षों का विश्लेषण किया है और वे इस बार कांग्रेस को वोट देंगे।

## दिल्ली चुनाव से पहले आप और कांग्रेस को राउत की सलाह

**मुंबई।** शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने मंगलवार को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के बीच तीखी लड़ाई पर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी और देश में लड़ाई भाजपा के खिलाफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। हालाँकि, विधानसभा चुनाव में जो स्थिति बनी है, उससे ऐसा लग रहा है कि वे भाजपा की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लड़ाई दिल्ली और देश में भाजपा के खिलाफ होनी चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि इंडिया ब्लॉक के दो सदस्यों का एक-दूसरे को नीचा दिखाना सही नहीं था। उन्होंने कहा कि जनता इस झगड़े को देख रही है और अगले लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह के व्यवहार के बारे में सवाल पूछेगी।

## आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी

**पटना।** बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में दो जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की मंगलवार सुबह तबीयत अचानक बिगड़ गई है। पटना के मेदांता अस्पताल के डाक्टरों की टीम पीके के स्वास्थ्य का जांच करने शेखपुरा हाउस पहुंची। हालत देखकर डॉक्टरों की टीम ने अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया। इसके बाद उनके समर्थकों ने उन्हें एंबुलेंस में लेकर मेदांता अस्पताल गई। यहां उनका इलाज जारी है। प्रशांत किशोर के समर्थकों का कहना है कि मंगलवार सुबह 10 बजे तक लोगों से बातचीत कर रहे थे। कुछ देर बाद अचानक वह अचेत हो गए। इसके बाद मुंह पर पानी के छींटें मारकर हम लोगों ने होश में लाया। फौरन डॉक्टरों को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हेंअस्पताल जाने की सलाह की। डिहाइड्रेशन समेत अन्य कुछ बातें समाने आई है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बता दें कि पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पटना पुलिस सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था।

# दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान

## 8 फरवरी को आएंगे नतीजे, इसके साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू

**नई दिल्ली।** चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी 2025 को मतदान होगा। 8 फरवरी 2025 को मतगणना होगी और इसी के साथ यह तय हो जाएगा कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है?

### दिल्ली में इस तरह है चुनाव कार्यक्रम

चुनाव की अधिसूचना- 10 जनवरी
नामांकन की आखिरी तारीख- 17 जनवरी
नामांकन पत्रों की जांच- 18 जनवरी
नाम वापसी का अंतिम दिन- 20 जनवरी
मतदान की तारीख- 5 फरवरी
मतगणना की तारीख- 8 फरवरी

### दुनिया के देशों में तो एक-एक महीने काउंटिंग चल रही है

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम पर यह सवाल उठाए गए कि शाम पांच बजे के बाद कैसे मतदान का आंकड़ा बढ़ जाता है? करोड़ों वोट कैसे बढ़ जाते हैं? यह ध्यान रखना होगा कि सुबह 9:30 बजे, 11:30, दोपहर 1:30, 3:30 और शाम 5:30 बजे के बीच सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान का आंकड़ा इकट्ठा करते हैं। वोटिंग खत्म होने के समय फॉर्म 17-सी दिया जाता है। जब शाम 7:30 बजे तक अधिकारी तक सारी मशीनें इकट्ठा करता है, तब उसके मतदान केंद्र का अंतिम आंकड़ा पता चल पाता है, जबकि हमसे कहा जाता है कि छह बजे ही आंकड़ा बता दें। लोग ये भूल जाते हैं कि दुनिया के बड़े देशों में तो एक-एक महीना मतगणना चल रही है।

### ईवीएम को नई बैटरी डालकर सील किया जाता है

उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ईवीएम में नई बैटरी डाली जाती है। उसी दिन उसे सील किया जाता है। जिस दिन मतदान होता है, उस दिन सील पोलिंग एजेंट के सामने तोड़ी जाती है। मॉक पोल किया जाता है। पोलिंग एजेंट रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन आया, कौन गया। किसमें कितने वोट पड़े, इसकी संख्या उनको दी जाती है। काउंटिंग के दिन भी पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। फॉर्म 17 सी से मिलान होता है। उसके बाद किसी भी पांच वीवीपैट से भी मिलान किया जाता है। हमारी प्रक्रिया पर कई बार सवाल उठाए गए हैं।

### फॉर्म सात के बिना नाम नहीं हटाया जा सकता : चुनाव आयोग

चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि भारतीय मतदाता बेहद जागरूक हैं। मतदाता सूचियों को लेकर अब भी कहानियां चल रही हैं। करीब 70 सीटें हैं। जिसमें राजनीतिक दल और उम्मीदवार हमारे साथ रहते हैं, जितने भी दावे और आपत्तियां आती हैं। उन्हें सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाता है। फॉर्म सात के बिना नाम नहीं हटाया जा सकता।

### ईवीएम मतगणना के लिए फुलप्रुफ डिवाइस : चुनाव आयोग

चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम में अविश्वसनीयता या किसी खामी का कोई सबूत नहीं है। ईवीएम में वायरस या बग आने का कोई सवाल ही नहीं है। ईवीएम में अवैध वोट होने का सवाल ही नहीं है। कोई धांधली संभव नहीं है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग-अलग फैसलों में लगातार यही कह रहे हैं और क्या कहा जा सकता है? ईवीएम मतगणना के लिए फुलप्रुफ डिवाइस है। टेम्परिंग के आरोप बेबुनियाद हैं। हम अभी बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव के समय हम नहीं बोलते।

उन्होंने कहा कि मतदाता मतदान का प्रतिशत बदलना असंभव है। कुछ मतदान दल आधी रात या अगले दिन रिपोर्ट करते हैं। गिनती से पहले फॉर्म 17सी का मिलान किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वीटीआर समझा न सके। यह पूरी तरह से समझाता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम बहुत जल्द ही 100 करोड़ मतदाताओं वाला देश बनने जा रहे हैं, मतदाताओं की कुल संख्या 99 करोड़ को पार कर चुकी है।

### अंतिम मतदाता सूची हो चुकी है जारी

चुनाव आयोग ने बीते सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम मतदाता सूची जारी की थी। इस चुनाव में दो लाख के करीब मतदाता 18 से 19 वर्ष के हैं। वह पहली बार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस सूची में कुल एक करोड़ 55,24,858 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाता 85,49,645 हैं, जबकि 71,73,952 महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर 1,261 हैं।

### प्रक्रिया के तहत नाम जोड़े और हटाए जाते हैं

चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची के लिए नाम प्रक्रिया के तहत जोड़े और हटाए जाते हैं। इसके लिए फॉर्म 6 और फॉर्म सात होता है। नामों के घटाने और जोड़ने की जानकारी समय-समय पर राजनीति दलों को दी जाती है।

### 1,67,329 नए मतदाता जुड़े

चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में एक महीने में 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक 1,35,089 मतदाताओं ने फॉर्म-6 और 83,825 ने फॉर्म-8 के तहत मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने, पता बदलने, नाम को सूची से हटाने और आपत्तियां और सुझाव के लिए आवेदन किया।

चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों ने सभी आवेदनों को 24 दिसंबर तक सुलझा दिया। इस तरह से अंतिम मतदाता सूची जारी होने तक 3,08,942 नए नाम मतदाता सूचियों में जुड़े। 1,41,613 नाम हटाए गए। इस दौरान कुल 1,67,329 मतदाता नए जुड़े।

### हर आवेदन को जांचा गया

चुनाव आयोग ने पाया की 16 दिसंबर से एक माह में 5.10 लाख नए लोगों ने अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया। ऐसा पहली बार हुआ। ऐसा तब हुआ, जबकि तय समय में तीन लाख से ज्यादा मतदाता नई सूची में जुड़ चुके थे क्योंकि ऐसा 20 दिन के भीतर हो रहा था, जब आपत्तियां, जांच का समय गुजर चुका था। यह तत्काल जांच का विषय था। सभी चुनाव पंजीकरण अधिकारियों- ईआरओ को जांच के लिए निर्देशित किया गया। हर आवेदन को जांचा गया। संबंधित अधिकारियों को सौ फीसदी सत्यापन के लिए कहा गया है।

## अमित शाह ने लॉन्च किया भारतपोल पोर्टल

# जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में मिलेगी मदद

**नई दिल्ली।** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश ने मंगलवार को विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए सीबीआई की ओर से विकसित भारतपोल पोर्टल को लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह आधुनिक सेवाओं के इस्तेमाल का वक्त है। इसलिए भारतपोल पोर्टल विकसित किया गया है। इससे सुरक्षित भारत बनाने का सपना पूरा होगा। सुरक्षा चुनौतियों से लड़ने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतपोल हमारे देश में अंतरराष्ट्रीय जांच को एक नए युग में ले जाएगा। सीबीआई इंटरपोल के साथ काम करने वाली एकमात्र एजेंसी थी, लेकिन भारतपोल से हर भारतीय एजेंसी और सभी राज्यों की पुलिस आसानी से इंटरपोल से जुड़ सकेगी। हम अंतर को पाटने और अपराध को नियंत्रित करने के लिए कुशलता से काम करने में सक्षम होंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतपोल पोर्टल से अंतरराष्ट्रीय डाटा का उपयोग करना आसान होगा। भगोड़े अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। इंटरपोल का डाटा भी हमारे पास होगा। अपराधियों को ट्रैक करने की व्यवस्था होगी। इस दौरान बेहतर काम करने पर 35 सीबीआई अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।

भारतपोल पोर्टल देश की जांच एजेंसियों को रियल टाइम सूचना साझा करने में सक्षम बनाएगा। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर यह समन्वय इंटरपोल लाइजनिंग ऑफिसर (आईएलओ) के जरिए किया जाता है, जो अपने-अपने संगठनों में पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों और शाखा प्रमुखों के स्तर पर यूनिट ऑफिसर से जुड़े होते हैं। मौजूदा समय में सीबीआई, आईएलओ और यूओ के बीच संचार का साधन पत्र, ईमेल और फैक्स है। भारतपोल पोर्टल बनने से एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर होने के साथ ही अपराधी को

पकड़ने में मदद मिलेगी।

नया अत्याधुनिक ऑनलाइन मंच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों को विदेश में छिपे भगोड़े व्यक्तियों या अन्य मामलों के बारे में इंटरपोल से सूचना मांगने के लिए अपने अनुरोध भेजने की सुविधा देगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है, जो इंटरपोल से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार है।

इंटरपोल के माध्यम से, सीबीआई भारत में अपराध या अपराधियों की जांच में सहायता के लिए इंटरपोल के अन्य सदस्य देशों की समान एजेंसियों से आवश्यक जानकारी मांग सकती है तथा अन्य देशों की सहायता के लिए आपराधिक डेटा और खुफिया जानकारी साझा कर सकती है।

### गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में मत्था टेका

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन त्याग, शौर्य और सेवा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अधर्म और अत्याचार के खिलाफ अडिग होकर संघर्ष किया। प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर शाह ने नई दिल्ली स्थित गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में मत्था टेककर सत्संग का आशीष भी प्राप्त किया।

खेल
प्रमुख समाचार

## चैंपियंस ट्रॉफी में शमी-हार्दिक की हो सकती है वापसी?

**नई दिल्ली।** चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तारीखें जैसे-जैसे नजदीक आ रही हैं, फैंस के मन में टीम चयन को लेकर उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। मिनी वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाने वाला यह टूर्नामेंट 19 फरवरी से पाकिस्तान और यूएई में खेला जाएगा। इसके लिए अभी तक भारतीय टीम का एलान नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हार के बाद चयनकर्ताओं के पास सोचने को काफी कुछ है। हालांकि, टेस्ट और वनडे में काफी अंतर है और अजीत अगरकर की अगुआई में चयनकर्ता इसके लिए जल्द ही टीम का एलान कर सकते हैं। हालांकि, पिछले साल जून के बाद भारतीय टीम ज्यादा वनडे खेली नहीं है।

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम सिर्फ एक वनडे सीरीज खेली है और उसमें भी श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया को हार मिली थी। तब चयनकर्ताओं ने बहुत नई टीम चुनी थी। हालांकि, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए चयनकर्ता ज्यादा प्रयोग करने के पक्ष में नहीं होंगे। रोहित शर्मा का कप्तान बनना तय है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों पर अभी भी संशय है। सबकी नजर जसप्रीत बुमराह की चोट पर है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का अभियान काफी हद तक उन पर निर्भर होगा। इसके अलावा मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या की वापसी पर भी सभी की नजरें होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम के एलान की अंतिम तारीख 12 जनवरी है। वहीं, इसमें फेरबदल करने की अनुमति 13 फरवरी तक होगी। श्रीलंका के खिलाफ पिछले साल हार्दिक को वनडे में उपकप्तानी से हटा दिया गया था और शुभमन गिल को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि, अब मीडिया रिपोर्ट्स में एक और बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, न तो हार्दिक और न ही गिल को उपकप्तानी सौंपी जाएगी। जसप्रीत बुमराह अगर फिट हुए तो उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

## सेंसेक्स 234 अंक चढ़ा निफ्टी 23,700 के पार

**नईदिल्ली।** घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी पिछले ट्रेडिंग सेशन में बड़ी गिरावट झेलने के बाद मंगलवार (7 जनवरी) को पॉजिटिव नॉट पर बंद हुए। सोमवार को सेंसेक्स और निफ़्टी 1.5% से ज्यादा गिर गये थे। यह पिछले तीन महीने में सेंसेक्स और निफ्टी की किसी एक ट्रेडिंग सेशन में सबसे बड़ी गिरावट थी। एनर्जी स्टॉक्स में तेजी से बाजार में उछाल देखने को मिला। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मंगलवार को 359.41 अंक चढ़कर 78,324.40 के लेवल पर खुला। अंत में यह 234.12 अंक या 0.30 प्रतिशत की बढ़त लेकर 78,199.11 अंक पर क्लोज हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ़्टी-50 भी 134.40 (0.57 प्रतिशत) अंकों की बढ़त के साथ 23,750.45 के स्तर पर ओपन हुआ। अंत में यह 91.85 अंक या 0.39 प्रतिशत की बढ़त लेकर 23,707.90 के स्तर पर सेटल हुआ।

## एचडीएफसी बैंक ने घटाई एमसीएलआर दरें

**नईदिल्ली।** नए साल की शुरुआत पर एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को खास तोहफा दिया है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक ने लोन की ब्याज दरों में मामूली लेकिन अहम कटौती की घोषणा की है। बैंक ने ओवरनाइट, 6 महीने, 1 साल और 3 साल की अवधि वाले लोन पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में 0.05% की कमी की है। हालांकि, बाकी अवधि वाले लोन की ब्याज दरें पहले जैसी ही बनी रहेंगी। यह नई दरें 7 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी हैं। एचडीएफसी बैंक की यह पहल नए साल में ग्राहकों को राहत देने और कर्जदारों के बोझ को हल्का करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। एचडीएफसी बैंक ने अपने एमसीएलआर में बदलाव किया है, जो 7 जनवरी 2025 से लागू होंगे।

## दूसरी तिमाही में मुनाफे से घाटे में आई मोबिक्विक कंपनी

**नईदिल्ली।** फिनटेक कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड ने मंगलवार (7 जनवरी) को अपनी दूसरी तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया। कंपनी पिछले महीने ही शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। मोबिक्विक ने बताया कि 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसे 3.6 करोड़ रुपये का नेट घाटा हुआ है। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी ने 5.2 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। मोबिक्विक ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में बताया कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन में सुधार से कंपनी का रेवेन्यू 2024-25 की सितम्बर तिमाही में सालाना आधार पर 42 प्रतिशत बढ़कर 293.66 करोड़ रुपये हो गया। यह एक साल पहले की इसी अवधि में यह 206 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में कुल खर्च भी बढ़कर 287 करोड़ रुपये हो गया।

## 2025 में ग्लोबल स्ट्रीमिंग का रह सकता है दबदबा!

**नईदिल्ली।** वीडियो स्ट्रीमिंग का कारोबार दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। इस साल पहली बार स्ट्रीमिंग वीडियो की कमाई (213 बिलियन डॉलर) पे-टीवी की कमाई (88 बिलियन डॉलर) से ज्यादा होगी। हर बड़े सब्सक्रिप्शन वाले स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अब विज्ञापन वाला प्लान शुरू कर दिया है, और फ्री मॉडल की तरफ यह रुझान बढ़ता रहेगा। आगे की बढ़त टीवी जैसे मॉडल पर निर्भर करेगी- डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग और प्रोग्रामिंग के मामले में। अमेरिका के पांच बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म - नेटफ्लिक्स, डिज्नी+, पैरामाउंट+, अमेज़न प्राइम वीडियो और मैक्स- अब पारंपरिक पे टीवी जैसा रूप लेने लगे हैं। लंदन की ग्लोबल एनालिस्ट फर्म ओमडिया के सीनियर एनालिस्ट टोनी गुन्नारसन ने कहा है कि ये सभी प्लेटफॉर्म विज्ञापन, खेलों की बड़ी रेंज और बंडल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अब 'पे टीवी 2.0' की तरह दिखने लगे हैं।

# नए समझौते अर्थव्यवस्था को देंगे नया आकार, बढ़ेगा विदेशों से व्यापार

**जयंतीलाल भंडारी**

यकीनन नए वर्ष 2025 में भारत के नए रणनीतिक व्यापार समझौते बढ़ेंगे। साथ ही बीते वर्ष 2024 में भारत की विभिन्न देशों के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी बनी है, उसके लाभदायक परिणाम भी दिखाई देंगे। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्यात को 800 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाने, विदेश व्यापार बढ़ाने और व्यापार घाटे में कमी लाए जाने के मद्देनजर सरकार के द्वारा इस समय विभिन्न देशों के साथ एक के बाद एक रणनीतिक द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और नए आकार लेते मुक्त व्यापार समझौतों का चमकीला परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है।

बीते साल 21 और 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा के दौरान आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, फिनटेक, बुनियादी ढांचे आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए गए। कुवैत खाड़ी देशों में भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। कुवैत भारत का छठा बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। वहीं, 16 दिसंबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके अपने सबसे पहले राजकीय विदेशी दौरे पर भारत आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लाभदायक द्विपक्षीय वार्ता की। दिसानायके ने 2022 के आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका के लोगों को भारत द्वारा किए गए सहयोग के लिए आभार जताया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा विकास व आर्थिक रोडमैप पर सहमति व्यक्त की। इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भारत के वैश्विक व्यापार और निर्यात बढ़ाने के मद्देनजर विदेश दौरों में द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं और व्यापार समझौतों की रणनीति लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। खासतौर से इस वर्ष पिछले छह महीनों में इस रणनीति से द्विपक्षीय व्यापार के अच्छे अध्याय लिखे गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने 16 से 21 नवंबर तक ब्राजील, नाइजीरिया व गुयाना के दौरे पर, जहां जी-20 शिखर सम्मेलन में भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता विषय पर प्रभावी संबोधन दिया, वहीं नाइजीरिया और गुयाना पहुंचकर इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की सार्थक वार्ताएं कीं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ब्राजील, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पुर्तगाल व स्पेन समेत कई देशों के नेताओं के साथ की गई 31 द्विपक्षीय और अनौपचारिक वार्ताओं में भारत का रणनीतिक महत्व उभरकर दिखाई दिया है।

उल्लेखनीय है कि रूस के कजान में 22 से 24 अक्तूबर तक आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने द्विपक्षीय वार्ताओं का रणनीतिक लाभ लिया। भारत और चीन के बीच पांच साल बाद अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों का नया अध्याय दिखाई दे रहा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि मोदी ने सितंबर में अमेरिका में आयोजित क्वाड लीडर्स सम्मेलन में भाग लेकर इस संगठन की भारत के लिए उपयोगिता बढ़ाई। वहीं, मोदी और जो बाइडन के बीच हुई बातचीत में कोलकाता में एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने का करार हुआ है। यह भी छोटी बात नहीं है कि गत नौ जुलाई को 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में मास्को में भारत और रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा के बाद भारत और रूस ने द्विपक्षीय कारोबार को 2030 तक 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने, व्यापार में संतुलन लाने, गैर-शुल्क व्यापार बाधाओं को दूर करने और यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू)-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र की संभावनाएं तलाशने का लक्ष्य रखा है।

हम उम्मीद करें कि सरकार वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच विभिन्न देशों के साथ जिस तरह द्विपक्षीय वार्ताओं, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और मुक्त व्यापार की डगर पर बढ़ रही है, उससे इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्यात के रिकॉर्ड लक्ष्य 800 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचने के साथ-साथ विदेश व्यापार बढ़ेगा और व्यापार घाटे में भी कमी लाई जा सकेगी।

# राजिम में बनेगी भक्तिन माता की भव्य कांस्य प्रतिमा

**रायपुर।** राजिम शैव और वैष्णव परंपरा का संगम स्थल है। राजिम के इस पवित्र स्थल में ही भगवान श्रीराम ने कुलेश्वर महादेव की स्थापना कर उनकी पूजा-अर्चना की थी। सोन्दूर, पैरी और महानदी के त्रिवेणी संगम के कारण यह क्षेत्र पूरे देश में प्रसिद्ध है। राजिम नगरी छत्तीसगढ़ का प्रयागराज के रूप में प्रसिद्ध है। यहां से प्रवाहित होने वाली महानदी पापमोचिनी गंगा कहलाती है। राजिम भक्तिन माता के नाम पर ही राजिम का नाम हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजिम में साहू समाज द्वारा आयोजित भक्तिन माता राजिम जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि हम आज उस भूमि में एकत्रित हुए हैं जहां भगवान राम ने माता सीता के साथ अपने चरण रखे। माता सीता ने यहां महादेव की पूजा अर्चना की और रेत से ही कुलेश्वर महादेव को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि राजिम भक्तिन माता ने जिस त्याग और तपस्या का उदाहरण प्रस्तुत किया, उसकी स्मृति साहू समाज संजोये हुए है। राजिम भक्तिन माता की जयंती से सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलता है। साथ ही उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। समाज के एकजुट होने से प्रदेश और देश को भी मजबूती मिलती है। उन्होंने इस अवसर पर राजिम में भक्तिन माता की भव्य कांस्य प्रतिमा की स्थापना के लिए 5 करोड़ रूपए की घोषणा की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि साहू समाज प्रगतिशील समाज है। यह समाज खेती किसानी के साथ-साथ व्यापार, उद्योग जगत में आगे बढ़ रहा है। साहू समाज अपनी विरासत को भी संजोये हुए हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति लेकर 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानकर उनके हित में 18-18 घंटे काम करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके समाज का गौरव हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के समय राजिम में भव्य कुंभ कल्प की शुरूआत हुई थी। पूर्ववर्ती सरकार ने इसकी गरिमा कम कर दी थी। हमारी सरकार ने राजिम कुंभ कल्प की गरिमा को पुनर्स्थापित किया है। पिछले साल राजिम कुंभ में देश भर से संत समागम हुआ। हम इस साल भी हम भव्य राजिम कुंभ कल्प का आयोजन करने जा रहे है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में माताओं और बहनों की उपस्थिति है। हमने महतारी वंदन योजना से महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया है। अभी हाल ही में इस योजना की ग्यारहवीं किश्त माता-बहनों के खाते में हस्तांतरित की गई है। पहली तारीख को माताओं-बहनों के मोबाइल में इस योजना की राशि जाती है और उनका चेहरा खिल जाता है। इससे उन्हें अपने बजट को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। जब भी मैं इस बारे में उनसे चर्चा करता हूँ वे बहुत खुश हो कर बताती हैं कि इस योजना से उनके जीवन में कितना बदलाव आया। सही मायने में तब लगता है कि हम अटल जी के सुशासन का सपना छत्तीसगढ़ में साकार कर रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उन्होंने अमेरिका प्रवास के दौरान देखा कि किस तरह विदेशों में भी साहू समाज के बच्चे छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं। अपनी कर्मठता और संकल्पशक्ति से साहू समाज के लोग देश-दुनिया में समाज का नाम उंचा कर रहे हैं। केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि भक्त माता करमा के नाम पर डाक टिकट जारी होना हम सब के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि करमा माता ने अपना जीवन समाज को समर्पित किया, उनके विचारों और आदर्शों से समाज का विकास हो सके इसलिए जरुरी है कि हम सभी उन विचारों को आत्मसात करें। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजिम पहुंचकर भगवान राजीव लोचन मंदिर में भक्तिन माता राजिम एवं भगवान राजीव लोचन की विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की।

## गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर

# राजनांदगांव को मिली 23 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की सौगात

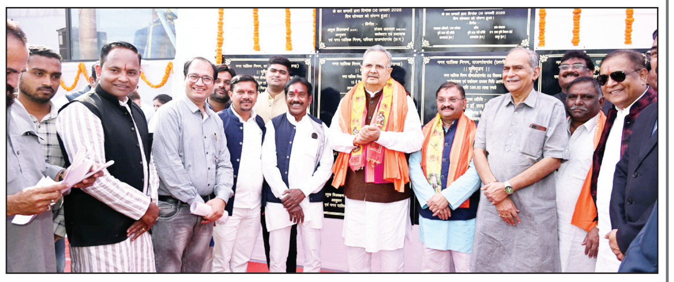

**राजनांदगांव।** विधानसभा अध्यक्ष व राजनांदगांव विधायक डॉ रमन सिंह जी के अथक प्रयासों से आज नगर पालिका निगम द्वारा 23 करोड़ 13 लाख 44 हजार रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया गया। यह ऐतिहासिक पहल राजनांदगांव की प्रगति को नई गति प्रदान करने और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।

**प्रमुख विकास कार्यों का विवरण:** अधोसंरचना मद- 42 मार्गों के डामरीकरण कार्य के लिए 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। यह पहल क्षेत्र में सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगी।

अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण निधि- 68 विकास कार्यों के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसमें सीसी रोड, तटबंध, शेड निर्माण, जिम उपकरण की स्थापना और अन्य अधोसंरचना कार्य शामिल हैं।

**15वें वित्त आयोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-** 16 स्क्रूसेंटर के तहत कंपोस्ट पीट शेड, बाउंड्री वॉल, पी.सी.सी. रोड निर्माण और नाली निर्माण जैसे कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0- 73 शौचालयों के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की गई है।

राजनांदगांव के नागरिकों ने विधानसभा अध्यक्ष और विधायक डॉ. रमन सिंह जी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों के लोकार्पण से आने वाले समय में क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। साथ ही, यह सभी कार्य राजनांदगांव को विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नागरिकों ने डॉ. रमन सिंह जी की दूरदृष्टि और प्रयासों की सराहना करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की।

इसके साथ ही आज गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव के विधायक डॉ. रमन सिंह ने खालसा पंथ के संस्थापक और सिख धर्म के 10वें गुरु, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को राजनांदगांव स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर गुरुजी को स्मरण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गुरुजी के विचारों और त्याग को नमन करते हुए समाज में एकता, समानता और सेवा की भावना को बढ़ावा देने की बात कही।

साथ ही, डॉ. रमन सिंह ने आज बालाजी ब्लड सेंटर के शुभारंभ कार्यक्रम में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर उन्होंने ब्लड सेंटर की स्थापना को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि यह सेंटर आपातकालीन स्थितियों में रक्त की आवश्यकता को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने ब्लड सेंटर की टीम को बधाई देते हुए समाज के हर वर्ग को इसमें सहयोग देने का आह्वान किया।

इस कार्यक्रम के दौरान विस अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि राजनांदगांव को सुशासन का आदर्श उदाहरण बनाया जाए। हमें विश्वास है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा और यह क्षेत्र विकास के नए आयामों को छूएगा। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के दिखाए गए मार्ग पर चलने और उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान भी किया।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राजनांदगांव के सांसद श्री संतोष पांडे जी, पूर्व सांसद श्री मधुसूदन यादव जी, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता गण, और बड़ी संख्या में राजनांदगांव के नागरिक उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक उत्साहपूर्ण और प्रभावशाली बना दिया।

# ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से कर रही कार्य: चौधरी

**रायपुर।** वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखण्ड अंतर्गत बाघाडोला, नवापारा-अ एवं छपोरा में 70 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसानों सहित सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। ग्रामीण अंचलों में जनसुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार कार्य किया जा रहा है। अधोसंरचना विकास के कार्य तेजी से आगे बढ़ाएं जा रहे है।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि सरकार गठन के उपरांत 18 लाख आवास निर्माण को स्वीकृति दी गई। इन आवासों का निर्माण पूरी तेजी से करवाया जा रहा है। पीएम आवास योजना से गरीबों के पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है। महतारी वंदन योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। उन्हें प्रतिमाह एक-एक हजार रूपये राशि उनके खाते में भेजी जा रही है। जिससे महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि अपने घर-परिवार में भी निर्णय लेने में बराबरी का हक महसूस कर रही हैं। इसके साथ ही विभिन्न जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए कृषक उन्नति योजना के माध्यम से दो साल का बोनस दिया गया। इसी तरह किसानों से 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल के मान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। रामलला दर्शन योजना के माध्यम से बुजुर्गो को अयोध्या धाम के दर्शन कराए जा रहे है।

वित्त मंत्री चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि सभी निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ किए जाए। इसमें समय-सीमा का भी विशेष ध्यान रखें। हमारा उद्देश्य लोगों को जनोपयोगी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी अपने दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करें। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने पुसौर विकासखण्ड के बाघाडोला, नावापारा-अ एवं छपोरा में 70 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें बाघाडोला में 25 लाख 40 हजार रुपये की लागत से 3 सीसी रोड निर्माण, 1 लाख 50 हजार रुपये की लागत से दर्री तालाब में पचरी निर्माण, 10 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन के पास शेड निर्माण शामिल है।

## नए वायरस का अटैक: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा

# विभाग किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से है तैयार

**रायपुर।** ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जिसे एचएमपीवी वायरस कहा जा रहा है, इससे निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से तैयार है। वायरस को लेकर सतर्कता बरतने और तैयारियों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय नवा रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

देश के कुछ हिस्सों में इस वायरस के मरीज मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों की टीम सतत रूप से इस वायरस के बारे में निगरानी रख रही है और इसके लक्षणों एवं प्रभाव के बारे में भी अध्ययन कर रही है। जायसवाल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना महामारी के बाद से ही किसी भी प्रकार के आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि इस वायरस को रोकें और साथ ही इससे लड़ने के लिए आम जनता को भी जागरूक करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह वायरस पहले भी रिपोर्ट किया जा चुका है और इससे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है । उन्होंने आम जनता से स्वच्छता पर जोर देने की बात कही है ।विशेषज्ञों के अनुसार एचएमपीवी वायरस से बचने के लिए भीड़ वाली जगह से दूरी बना कर रखें, सर्दी खांसी बुखार वाले मरीजों के के संपर्क में नहीं आएं, सर्दी खांसी बुखार के लक्षण पर तत्काल स्थानीय अस्पताल में जांच कराएं। ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। खांसते व छींकते समय मुंह व नाक को रूमाल से ढंके, अपने हाथों को साबुन एवं सेनेटाइजर से साफ करते रहें।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

## किसानों को धान की कीमत 3100 रु क्विंटल नहीं दे रही: बैज

**रायपुर।** प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की सरकार किसानों से 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी कर रही है और उसी दर से किसानों को भुगतान कर रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में किसानों से वादा किया था धान के खरीदी 3100 रु क्विंटल की दर से की जाएगी और एकमुश्त भुगतान ग्राम पंचायत भवन में किसानों को नगद किया जाएगा।

जो अब तक धान खरीदी के दौरान कहीं देखने को नहीं मिला है, यह किसानों के साथ धोखा है और भाजपा का चरित्र वादाखिलाफी करना है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि किसान धान बेचने आज भी भटक रहे, उन्हें बारदाना नहीं मिल पा रहा है, टोकन नहीं दिया जा रहा है, धान खरीदी केंद्रों में धान जमा हो गया है, कस्टम मिलिंग हो नहीं पा रहा है। प्रदेश के कई धान केंद्रों में एक सप्ताह से अधिक हो गया है धान की खरीदी नहीं हो रही है। सरकार फर्जी और गुमराह करने वाले आंकड़े जारी करके धान खरीदी को बेहतर बता रही है और खुद के हाथ से पीठ थपथपा रही है जबकि किसान हताश और परेशान धान खरीदी केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा का चरित्र ही धोखा बाजी है।

## निकाय चुनाव: पिछली जीत के रिकार्ड को तोड़ेगी: शुक्ला

**रायपुर।** नगरीय निकाय चुनावों के लिये नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया है, कांग्रेस ने इन स्थानीय निकाय के चुनावों में न सिर्फ अपनी पिछली जीत दोहरायेगी, अबकी बार और अधिक निकाय क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत कर आयेंगे। प्रदेश कांग्रेस

संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अधिकांश नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में जीत हासिल किया था। प्रदेश में भाजपा की सरकार के खिलाफ वातारण है। लोग प्रदेश की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, रोज हो रही हत्याओं, बलात्कार, लूट, चाकूबाजी की घटनाओं के कारण सरकार से निराश है, भाजपा की साय सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में जनता को निराश किया है। विचु के समय भाजपा ने जनता से जो वादा किया था, एक साल में उसको पूरा नहीं किया है। न 500 रू. सिलेंडर देने का वादा पूरा किया और न ही 18 लाख आवास देने का वादा पूरा किया। भाजपा राज में बिजली के दाम बढ़ गये है। कांग्रेस शासनकाल में 400 यूनिट तक बिजली के दामों में 50 प्रतिशत छूट को भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है।

## उपभोक्ताओं को कैसे वंचित कर सकती है: ठाकुर

**रायपुर।** प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों को डीजल खरीदी में 6.50 रु प्रति लीटर छूट दे सकती हैं तो आम उपभोक्ताओं क्यों नहीं? डीजल, पेट्रोल की महंगाई से हर वर्ग पीड़ित हैं। ऐसे में सरकार को वैट में छूट सभी को देना चाहिये। एक राज्य में डीजल में वैट की दो दरें कैसे हो सकती हैं? सरकार गरीब आदमी, किसान, ट्रांसपोर्ट

व्यवसायी, बस, टैक्सी, होटल व्यवसायी, कार, ट्रैक्टर, सहित डीजल का उपयोग करने वाले आम जनता को भी डीजल खरीदी में छूट से कैसे वंचित कर सकती हैं? प्रदेश सरकार ने उद्योगपतियों को डीजल खरीदी में वैट टैक्स में 7 प्रतिशत राहत दिया है, 24 प्रतिशत की जगह उनसे 17 प्रतिशत वैट लिया जायेगा। उद्योगपतियों के अलावा अन्य वर्ग को डीजल में 24 प्रतिशत वैट देना होगा। ये अन्याय है। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती हैं लेकिन इनकी नीतियां खास वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली ही रहती हैं। किसानों को लेकर भाजपा सरकार का रवैया विरोधी ही रहा हैं। प्रदेश की तीन करोड़ आबादी को सामने रखकर सरकार को फैसला करना चाहिए। सरकार तत्काल डीजल में 17 प्रतिशत वैट सभी के लिए लागू करे। गरीब जनता को लूटना बंद करे।

## डिजिटलाइजेशन के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी: वर्मा

**रायपुर।** प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि कंप्यूटरीकरण के नाम पर राजस्व विभाग के त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के चलते अनेकों भूमि स्वामी के नाम, खसरा, खतौनी एवं नक्शे में भारी गड़बड़ी की शिकायतें हैं। कई किसानों की शिकायत है कि उनकी कृषि भूमि का रकबा कम या गायब कर दिया गया है। रिकॉर्ड सुधरवाने के

लिए किसानों को तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़े रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। राजस्व विभाग द्वारा राजस्व अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। कम्प्यूटरीकरण से राजस्व अभिलेखों में कई तरह की त्रुटियां सामने आई हैं जिनका तत्काल शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि आमतौर पर किसान ऋण पुस्तिका में दर्ज़ रकबा को अपने द्वारा धारित भूमि का प्रमाण मानता है, लेकिन अब रिकॉर्ड को ऑन लाइन देखने पर त्रुटियां सामने आ रही हैं। आधार कार्ड और भू-राजस्व रिकॉर्ड के नाम में अंतर होने से किसान प्रधानमंत्री किसान योजना, फसल बीमा योजना जैसे अनेकों सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। फौती नामांतरण में भू-अभिलेख रिकार्ड में बहुत से भूमि-स्वामी ऐसे दर्ज हैं, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है।

## युवा और खेल समिति की बैठक में शामिल हुए बृजमोहन

**नई दिल्ली/ रायपुर ।** रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को राज्यसभा सचिवालय में आयोजित संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और निपुण भारत मिशन को सम्मिलित करते हुए शिक्षा, महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण

विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव एवं अन्य प्रतिनिधियों ने आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार पर अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही केन्द्रीय विद्यालय संगठन , नवोदय विद्यालय संगठन , केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जैसी स्वायत्त संस्थाओं के कार्यकरण पर चर्चा की गई। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने शिक्षा के शुरुआती वर्षों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग , केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और अन्य निकायों के कार्यकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

## राजभवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया अनेक राज्यों का स्थापना दिवस

# हर राज्य की अपनी एक विशिष्ट पहचान है :राज्यपाल

**रायपुर।** राजभवन में आज कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख राज्यों का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने इस अवसर पर कहा कि भारत विभिन्न रंगों के अनेक पुष्पों की एक माला है। हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है। इन राज्यों के लोग अपनी विशिष्ट पहचान के साथ छत्तीसगढ़ में निवास करते हुए व्यवसाय या नौकरी कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई केन्द्र सरकार के एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक-दूसरे राज्यों का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसी कड़ी में राजभवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। राज्यपाल ने स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बधाई दी।

कार्यक्रम में राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि इस कार्यक्रम के पीछे का विचार, विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान का आदान-प्रदान करना है, जो आपसी समझ और सद्भाव को बढ़ावा देगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। इस परिप्रेक्ष्य में आज का कार्यक्रम एक गौरवपूर्ण क्षण है।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि हर राज्य का स्थापना दिवस, उस राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होता है। राज्य की समृद्धि और विकास का गवाह यह दिन हमें अपने राज्य की स्थापना के मूल उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों का स्थापना दिवस, केवल उनके विकास की यात्रा का उत्सव नहीं है बल्कि भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है। राज्यपाल श्री डेका ने विभिन्न राज्यों की विशेषताओं को रेखांकित किया। माटी का स्वर्ग, कर्नाटक अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति के साथ-साथ भाषा और साहित्य में समृद्ध है। यह राज्य कन्नड़ साहित्यकारों और कवियों का घर है, जिन्होंने भारतीय साहित्य को अद्वितीय ऊंचाईयां प्रदान की है। तमिलनाडु राज्य के संबंध में कहा कि यह भारत की द्रविड़ सभ्यता का केंद्र है जो अपनी कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य, आध्यात्मिक धरोहर के लिए विख्यात है। इस राज्य ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिल्ली के संबंध में कहा कि यह हमारी राजधानी ही नहीं बल्कि देश का दिल भी है।

# कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी कर्मचारियों की समस्याएं, निराकरण के दिए निर्देश

**बिलासपुर।** कलेक्टर अवनीश शरण ने आज कर्मचारी जनदर्शन में पहुंचे अधिकारी-कर्मचारियों की समस्याओं को इत्मीनान से सुना। इस दौरान अधिकारी-कर्मचारियों ने भी अपनी समस्याएं खुलकर कलेक्टर के समक्ष रखी। कलेक्टर ने आवेदन संबंधित अधिकारियों को भेजते हुए जल्द निराकरण के निर्देश दिए।

साप्ताहिक जनदर्शन में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुख्य शाखा बिलासपुर में सहायक लेखापाल के पद पर कार्यरत कर्मचारी श्रीमती राजकिशोरी एक्का ने पदोन्नति हेतु बंद लिफाफा खोलने कलेक्टर को आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि 2017 में हुई पदोन्नति में उनका नाम शामिल है, लेकिन पदोन्नित हेतु बंद लिफाफा अभी तक नहीं खोला गया है। कलेक्टर ने आवेदन सीईओ को भेजा। विकासखंड तखतपुर के शासकीय प्राथमिक बालक शाला भरनी में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत रामकुमार कौशिक द्वारा वेतन बहाल कराने आवेदन दिया गया। उन्होंने बताया कि संबंधित बैंक द्वारा बिना कारण बताए खाता संचालन पर रोक लगा दी गई है।

विकासखंड कोटा के शासकीय प्राथमिक शाला पीपरतराई में कार्यरत सहायक शिक्षिका श्रीमती चुलेश जांगड़े द्वारा पारिवारिक कारणों से वर्तमान स्थान से पोस्टिंग विकासखंड तखतपुर के शासकीय प्राथमिक शाला शांतिनगर उसलापुर में कराने हेतु कलेक्टर को आवेदन दिया। कलेक्टर ने आवेदन आवश्यक कार्रवाई के लिए डीईओ को भेजा। जनपद पंचायत मस्तूरी में कलेक्टर दर से कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत मनोज कुमार पाण्डेय ने बिना सूचना दिए ऑपरेटर के कार्य से बेदखल करने की शिकायत कलेक्टर से की।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर ( छ.ग. ) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर ( छ.ग. ) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.